

अनुगामिनी

महबूबा मुफ्ती घर में नजरबंद 3 कुपोषण अक्सर ज्ञान की कमी का परिणाम होता है : पीएम मोदी 8

पाकिम हवाई अड्डे से कोलकाता के लिए अतिरिक्त उड़ान



अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 12 अप्रैल। सिक्किम के पर्यटकीय मौसम को ध्यान में रखते हुए स्पाइस जेट ने कोलकाता से पाकिम तक की यात्रा के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू की हैं। कोलकाता-पाकिम की एक दैनिक उड़ान थी लेकिन सोमवार से दो उड़ानें शुरू की गई हैं। दिल्ली से पाकिम तक की यात्रा के लिए पहले की तरह एक ही फ्लाइट है। पाकिम विमान स्थल के निदेशक रामतानु शाह ने पुष्टि की कि स्पाइसजेट की अतिरिक्त सेवा 25 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगी।

गौरतलब है कि सिक्किम के नज्दकी बागडोगरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के हवाईपट्टी की मरम्मत शुरू होने के पश्चात सोमवार से सभी उड़ानें निलंबित हैं जिसके दबाव को ध्यान में रखते हुए पाकिम हवाईअड्डे पर अतिरिक्त उड़ानें शुरू की गई हैं। निदेशक शाह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अतिरिक्त हवाई सेवा सुबह 11.30 बजे आकर दोपहर 12 बजे लौट रही है जबकि सामान्य सेवा 12.30 बजे पहुंचकर 1 बजे लौट रही है। वहीं यह सेवा नियमित रूप से संचालित होगी या नहीं यह मौसम पर निर्भर करेगा।

धारा विकास पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न



अनुगामिनी नि.सं.

नामची, 12 अप्रैल। जल स्रोतों के कार्यालय हेतु प्रशिक्षण व तकनीकी जानकारी प्रदान करने तथा सामुदायिक विकास के लिये जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज प्रदेश संस्थान, कारफेक्टर द्वारा 11 से 13 अप्रैल तक नामची नगर परिषद सभागार में 'सामुदायिक जलस्रोत प्रबंधन तथा विकास (धारा विकास)' विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामची प्रखंड प्रशासनिक केंद्र के अधीन पांच ग्राम पंचायत इकाईयों दामथांग, असांगथांग, मिर्कोला-सिधीथांग, बूटार-सालेबोंग तथा मणिराम-फालीडारा; के पंचायत सदस्य, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति तथा संयुक्त वन प्रबंधन समिति के लोग हिस्सा ले रहे हैं। एसआईआर डीएंडपीआर, कारफेक्टर की फील्ड फेसिलिटेटर श्रीमती संगीता प्रधान के स्वागत भाषण से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। कार्यक्रम के पहले दिन नामची बीएसी के बीडीओ तेनजिमा भूटिया मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में जल स्रोतों के सूखने तथा उससे भविष्य में होने वाली समस्याओं के बारे में प्रकाश डाला। उनके अनुसार धारा विकास जैसे पहलों के माध्यम से जल स्रोतों का कायाकल्प करना बहुत अच्छा कदम है। इस दिशा में उन्होंने रूफ वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक के माध्यम से बारिश के पानी का संग्रह को एक महत्वपूर्ण, बहुत प्रभावी तथा आवश्यक तकनीक बताया। उद्घाटन सत्र के बाद एसआईआर डीएंडपीआर, कारफेक्टर के फील्ड फेसिलिटेटर कर्ण बहादुर छेत्री ने पहला तकनीकी सत्र प्रस्तुत किया। 'धारा विकास'

विषयक इस सत्र में उन्होंने धारा विकास के माध्यम से जल स्रोतों के कायाकल्प की पद्धतियों, स्रोतों में जल की उपलब्धता पर चट्टान गठन का प्रभाव तथा विभिन्न उपकरणों द्वारा वाटर टेबल बढ़ान जैसे विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से प्रस्तुत दी। दूसरे सत्र में 'जल जीवन मिशन' विषय पर नामची बीएसी के जुनियर इंजीनियर शुभम श्रेष्ठ ने वक्तव्य रखा। उन्होंने मिशन की विभिन्न खूबियों पर प्रकाश डाला। वहीं एसआईआर डीएंडपीआर, कारफेक्टर की फील्ड फेसिलिटेटर श्रीमती संगीता प्रधान ने 'जल तथा जीवन' विषय पर तीसरा तथा अंतिम सत्र प्रस्तुत किया। अपने वक्तव्य में उन्होंने जल के विभिन्न स्वरूपों, इसके प्रदूषण तथा इन जल स्रोतों की सुरक्षा पद्धतियों के बारे में जानकारी दी। श्रीमती प्रधान के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।

जिलाधिकारी ने की आपदा तैयारियों को लेकर समन्वय बैठक



अनुगामिनी का.सं.

पाकिम, 12 अप्रैल। पाकिम जिला कलेक्टर तारी छोपेल ने आज जिला प्रशासनिक केंद्र में आपदा तैयारियों के समन्वय हेतु एक बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य भूस्खलन, बाढ़, मानसून की बारिश, वृक्ष गिरने जैसे खतरों से निपटने हेतु सम्बंधित विभागों को तैयार करना था। बैठक की शुरुआत में डीसी ने आसन्न मानसून के दिनों में जिला प्रशासन को पूरी तरह तैयार रहने पर बल दिया। वहीं उन्होंने सड़कों की हालत, आपातकाल के दौरान उपकरणों तथा मानवशक्ति की उपलब्धता, बिजली कटौती एवं अन्य मसलों पर सम्बंधित विभागों के अधिकारियों से बातचीत की। वहीं बैठक में सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मियों ने आपदा से निपटने में अपनी पूरी तैयारी की बात कही और इस दिशा में सभी विभागों के आपसी समन्वय की भी जानकारी दी। बैठक में डीसी पाकिम के अलावा पाकिम पुलिस अधीक्षक, एडीसी (शेष पृष्ठ ०३ पर)

स्कूल प्रबंधन समिति की समन्वय बैठक आयोजित



सरोज गुरुंग

सोरेंग, 12 अप्रैल। जिले के टिम्बुरबुंग सरकारी माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को स्कूल प्रबंधन समिति, स्थानीय पंचायत, अभिभावक, शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ विद्यार्थियों की एक समन्वय बैठक के साथ ही अभिनन्दन कार्यक्रम आयोजित हुआ। राज्य के खेलकूद व युवा मामलों के सलाहकार मेघनाथ सुब्बा की अध्यक्षता में हुए उक्त कार्यक्रम में उनके अलावा शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक इचिंग सुब्बा, स्थानीय पंचायत सभापति, सम्बंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक डीएच सुब्बा, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरुंग के

छात्रवृत्ति 2022 के लिये चुनी गयी छात्रा अर्पणा सुब्बा शामिल रहे। इस दौरान कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में बताते हुए स्कूल के प्रधानाध्यापक डीएच सुब्बा ने स्कूल द्वारा प्राप्त उपलब्धियों एवं भावी कार्ययोजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने स्कूल के विकास हेतु स्कूल प्रबंधन समिति, शिक्षक-शिक्षिकाओं, अभिभावकों और विद्यार्थियों के बीच सठिक समन्वय व अनुशासन की जरूरत बतायी। वहीं कार्यक्रम में रिसोर्स स्पीकर के तौर पर उपस्थित सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक एसडी दहाल ने शिक्षा में आध्यात्मिकता की जरूरत बतायी। कार्यक्रम को सभाध्यक्ष सलाहकार मेघनाथ सुब्बा, सहायक शिक्षा निदेशक इचिंग सुब्बा के अलावा वरिष्ठ शिक्षक ओपी दहाल ने भी सम्बोधित किया।

एनसीआर के कई स्कूल कोरोना की चपेट में छात्र-शिक्षक संक्रमित मिलने के बाद तीन और स्कूलों में लगा ताला

राजेश अलख

नोएडा, 12 अप्रैल। दिल्ली-एनसीआर में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। गाजियाबाद और नोएडा के स्कूलों में कोरोना ने दस्तक दे दिया है। जिससे कई स्कूल कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। एनसीआर के डीपीएस, मिलेनियम और श्रीराम मिलेनियम स्कूल में छात्र और शिक्षक कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिसके बाद से स्कूल को बंद कर दिया गया है। नोएडा सेक्टर-40 स्थित एक निजी स्कूल के 13 विद्यार्थी और तीन शिक्षक कोरोना संक्रमित मिले हैं। शिक्षकों और बच्चों के संक्रमित होने के बाद 17 अप्रैल तक स्कूल बंद कर दिया गया है। स्कूल की ओर से संक्रमितों विद्यार्थियों व शिक्षकों की लिस्ट और उठाए गए कदमों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को भेजी गई है। स्कूल प्रबंधन ने परिसर सैनियटाइज करकर अन्य सुरक्षा उपाय अपनाने की बात कही है। वहीं पिछले करीब 10 दिनों से खाली पड़े सेक्टर-39 के कोविड अस्पताल में रविवार को 12 वर्षीय बच्ची को भर्ती कराया गया है। संक्रमण की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अब कक्षाएं ऑफलाइन न होकर ऑनलाइन चलेंगी। स्कूल प्रबंधक राजीव गुप्ता ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। कोविड मामले सामने आने के बाद स्कूल बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई है। स्कूल खुलने के बाद कोविड टेस्ट के आधार पर ही विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। साथ ही कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय अपनाया जाएगा। नोएडा के निजी स्कूल में कोविड मामले सामने आने के बाद अभिभावकों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं।

स्कूल प्रबंधन ने परिसर सैनियटाइज करकर अन्य सुरक्षा उपाय अपनाने की बात कही है। वहीं पिछले करीब 10 दिनों से खाली पड़े सेक्टर-39 के कोविड अस्पताल में रविवार को 12 वर्षीय बच्ची को भर्ती कराया गया है। संक्रमण की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अब कक्षाएं ऑफलाइन न होकर ऑनलाइन चलेंगी। स्कूल प्रबंधक राजीव गुप्ता ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। कोविड मामले सामने आने के बाद स्कूल बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई है। स्कूल खुलने के बाद कोविड टेस्ट के आधार पर ही विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। साथ ही कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय अपनाया जाएगा। नोएडा के निजी स्कूल में कोविड मामले सामने आने के बाद अभिभावकों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं।



स्कूल के अभिभावक अभी से ही ऑनलाइन क्लास शुरू करने की मांग करने लगे हैं। इसके साथ ही बच्चों की जांच, सुरक्षा आदि को लेकर अभिभावकों की सक्रियता बढ़ गई है। संक्रमित बच्चों के अभिभावक जहां इलाज की व्यवस्थाओं में लगे हैं। वहीं उनके साथ पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक की कोविड जांच करवाकर अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं।

एके नाइट्स गंगटोक ने बनाई सेमीफाइनल में जगह



सरोज गुरुंग

सोरेंग, 12 अप्रैल। सोरेंग में सिगलिंग स्पोर्टिंग क्लब के तत्वावधान में हो रहे ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट के तीसरे क्वार्टरफाइनल मैच में एके नाइट्स गंगटोक ने सिक्किम फुटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन को एक के मुकाबले दो गोलों से पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मैच की शुरुआत के 5वें मिनट में ही एके नाइट्स गंगटोक के जोन छिरिंग लेप्चा (7) ने खूबसूरत गोल कर अपनी टीम को बढ़त दिला दी। लेकिन यह बढ़त अधिक समय तक नहीं चली और खेल में जोरदार वापसी करते हुए सिक्किम फुटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन ने 16वें मिनट में संजय छोपेल (11) के आकर्षक गोल से मैच में बराबरी कर ली। हालांकि उसके बाद मैच के 40वें मिनट में एके अकादमी के स्ट्राइकर बुद्धराज (17) ने गोल कर टीम को पहले हाफ में 2-1 की बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन उसके बावजूद मैच गोलरहित समाप्त हुआ। 2-1 गोल के साथ एके नाइट्स ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। आज हुए मैच में जॉन छिरिंग लेप्चा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। आज फुटबॉल प्रतियोगिता के तीसरे दिन खेले गये मैच में स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम के चेयरमैन डीबी गुरुंग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनके साथ ही सिक्किम राज्य व्यापार निगम के सलाहकार निमतेम्बा भूटिया कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि थे। इनके अलावा मैच में पशुपालन एवं चिकित्सक सेवा सलाहकार सुधन प्रधान, पीएचई विभाग अध्यक्ष हरि नारायण सुवेदी, एसकेएम पार्टी के दरमदीन समष्टि अध्यक्ष टिकहांग सुब्बा, पूर्व

अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी पुष्पा छेत्री, प्रतियोगिता आयोजन समिति के अध्यक्ष अभिषेक पाण्डेय समेत क्लब के सभी सदस्य तथा आम लोगों की व्यापक उपस्थिति रही। गौरतलब है कि सोरेंग स्कूल खेल मैदान में हो रहे इस टूर्नामेंट में सिक्किम के अलावा अन्य राज्यों की आठ प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लबों ने भाग लिया है। इनमें आक्रमण एफसी गंगटोक, सिलीगुड़ी कंचनजंघा एफसी, एके अकादमी नाइट गंगटोक, संजु फुटबॉल अकादमी सोमबारे, जॉर्ज एफसी कालिम्पोंग, यूनाइटेड ब्रदर्स कालिम्पोंग, रेड पांडा नामची और फुटबॉल खलेयर्स एसोसिएशन ऑफ सिक्किम शामिल हैं। आयोजन समिति की ओर से बताया गया कि इस प्रतियोगिता के विजेता क्लब को दो लाख और उपविजेता क्लब को एक लाख की रूपये नकद राशि के अलावा आकर्षक ट्रॉफी प्रदान की जायेगी। इसके अलावा प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और फाइनल मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भी आकर्षक ट्रॉफियों से सम्मानित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि सिगलिंग स्पोर्टिंग एसोसिएशन की स्थापना 2015 में हुई थी। क्लब के अध्यक्ष अभिषेक पाण्डेय ने कहा कि स्थानीय उभरती प्रतिभाओं को फुटबॉल खेल के प्रति प्रेरित करना ही इस प्रतियोगिता के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही प्रतियोगिता में प्रतिष्ठित क्लबों के खिलाड़ियों की भागीदारी से स्थानीय प्रतिभावान खिलाड़ियों को सीखने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिता में आक्रमण फुटबॉल क्लब गंगटोक और जॉर्ज एफसी कालिम्पोंग पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 18 अप्रैल को खेला जायेगा।

सेना का एकीकृत फायर पावर प्रशिक्षण अभियान सम्पन्न



प्रवीण खालिंग

गंगटोक, 12 अप्रैल। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने आज सिलीगुड़ी के निकट तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज (टीएफएफआर) में एक्स कृपाण शक्ति नामक एकीकृत फायर पावर प्रशिक्षण अभियान का आयोजन किया। इसका उद्देश्य युद्ध के दौरान भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के समन्वय तथा पारदर्शिता के साथ तेज प्रतिक्रिया कर दुश्मन के छेड़ छुड़ा सकने की अपनी क्षमताओं को आंकना था। इस आयोजन स्थल को वास्तविक युद्ध क्षेत्र का चेहरा प्रदान करने हेतु पूरी तैयारियां की गयी थीं। जानकारी के अनुसार भारतीय सेना के नयी अवधारणा 'इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप (आईबीजी)' पारदर्शिता के साथ कितनी तेज प्रतिक्रिया कर दुश्मन के छेड़ छुड़ा सकती है, उसके प्रदर्शन हेतु ही आज सावगांव बस्ती के निकट तिस्ता नदी के बीचोंबीच बोफोर्स तोप के गोलों के साथ ही 81मीमी. मोर्टार, 84मीमी. रॉकेट लांचर, 7.6 मीमी. लाइट मशीन गन, एके-47, बीएफके टैंक और हरेक मिनट 96 राउंड फायरिंग करने में सक्षम रूद्र हेलीकॉप्टर के पराक्रम का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही आज के सैन्य प्रशिक्षण अभियान में 'सेंसर टू स्टूर विचारधारा का भी सफल प्रयोग देखा गया। प्रशिक्षण की समाप्ति पर सेना द्वारा हथियारों की एक प्रदर्शनी भी आयोजित हुई। त्रिशक्ति कोर के जनरल ऑफिसर कर्मांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच (एवीएसएम) इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके अलावा प्रदर्शनी में बीएसएफ, एसएसबी, स्थानीय नागरिक प्रशासन के साथ ही स्कूली बच्चे तथा एनसीसी के कैडेट भी शामिल हुए। सेना की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि दुश्मन सेना से देश की सुरक्षा हेतु भारतीय सेना प्रतिबद्ध है। सेना पर देशवासियों की अटूट आस्था और विश्वास को बनाये रखने हेतु ही प्रशासन और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ समन्वय में आज भारतीय सेना द्वारा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

राज्यपाल ने की पद्मश्री डॉ. एस.एन. आर्य से मुलाकात



अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 12 अप्रैल। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने आज पटना के प्रख्यात चिकित्सक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉ. एसएन आर्या से उनके आवास पर मुलाकात की। इस सुखद भेंट के दौरान राज्यपाल ने बीते दिनों की कई यादगार क्षणों को याद करते हुए उनके सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की। अचानक हुई इस भेंट से डॉ आर्या अत्यंत प्रसन्न हुए तथा अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि माननीय राज्यपाल महोदय के व्यवहार में तनिक भी बदलाव नहीं आया है, वे आज भी सदा की भांति सरल एवं सहज हैं। इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि व्यक्ति की पहचान पद से नहीं बल्कि उनके विचारों, व्यवहार एवं कार्यकुशलता से होती है।

देश के बाहर पहुंच बढ़ाने के लिए बीजेपी का प्लान, 150 देशों के राजदूतों से होगी बात

नई दिल्ली, 12 अप्रैल (एजेन्सी)। भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने सबसे स्वर्णिम दौर में है। हाल ही में पार्टी ने अपना 42वां स्थापना दिवस है। इसी कड़ी में अब पार्टी ने फैसला किया है कि वह देश के बाहर अपनी पहुंच बढ़ाएगी और आने वाले महीनों में पार्टी 150 से अधिक देशों के राजदूतों से जुड़ने की योजना बना रही है। इसके लिए भाजपा ने बकायदा प्लान भी तैयार किया हुआ है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए भाजपा के विदेश मामलों का विभाग सक्रिय हो चुका है। दरअसल, न्यूज एजेंसी एनआई ने भाजपा के विदेश मामलों के विभाग के प्रमुख डॉ विजय चौधरीवाले के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि

इसके लिए पार्टी ने राजदूतों को 8-9 समूहों में विभाजित किया है, प्रत्येक समूह में लगभग 10-15 राजदूत हैं। इन्हें अफ्रीकी, पूर्वी एशियाई, खाड़ी, राष्ट्रमंडल और उत्तरी अमेरिकी देशों सहित समूहों में विभाजित किया गया है। विजय चौधरीवाले ने बताया कि दुनिया को यह बताने का प्रयास है कि जनसंघ के युग से लेकर भाजपा के गठन तक भाजपा का क्या मतलब है। एक राष्ट्र के बारे में अपने विचार, अपनी विचारधारा और मार्गदर्शक सिद्धांत के साथ हम कौन सी सामाजिक गतिविधियां करते हैं, यह बताने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें 6 अप्रैल को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और इसे आगे बढ़ाते हुए हम आने वाले समय में 150 से अधिक राजदूतों के साथ बातचीत

करना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि भाजपा एक अलग पार्टी है और पार्टी के उत्थान और इस महान राष्ट्र के निर्माण में इसके योगदान के बारे में सभी को बताने की जरूरत है। आखिर हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। हम एक ऐसी पार्टी हैं जिसके पास चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में मौजूद सदस्यों की संख्या लगभग दोगुनी है। इससे पहले 6 अप्रैल, 2022 को भारतीय जनता पार्टी के 42 वें स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा ने एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में आए 15 राजदूतों के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बातचीत की



और पार्टी और उसकी विचारधारा के बारे में चर्चा की। बातचीत के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजदूतों को बताया कि भाजपा सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के सिद्धांतों के साथ काम किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्यक्रम के जरिए सिंगापुर के राजदूत यह देखना चाहते थे कि

भूमि अधिग्रहण का काम लगभग पूरा, भारत में जल्द साकार होगा बुलेट ट्रेन का सपना



नई दिल्ली, 12 अप्रैल (एजेन्सी)। जापान की हाईस्पीड ट्रेन शिकानसेन को भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ढाला जा रहा है। शिकानसेन ट्रेन में भारत के तापमान, धूल और भार के हिसाब से बदलाव किया जा रहा है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सतीश अग्रिहोत्री ने कहा कि बुलेट ट्रेन का सबसे पहला ट्रायल 2026 तक गुजरात के सूरत-बिलीमोरा खंड पर शुरू किया जाएगा। देश में पहली बुलेट ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी। अग्रिहोत्री ने बताया कि मुंबई-अहमदाबाद के बीच कुल 502 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसमें से गुजरात राज्य के भीतर 352 किलोमीटर की पटरी बिछाई जानी

है। इसके लिए 98.7 फीसदी भूमि अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया गया है। सूरत-नवसारी खंड पर बुलेट ट्रेन परियोजना के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद सतीश अग्रिहोत्री ने पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना का काम सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इस मौके पर जापान के राजदूत सातोसी सिजुकी भी मौजूद थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को प्रतिदिन परियोजना की कार्य प्रगति रिपोर्ट भेजी जाती है। अग्रिहोत्री ने एक सवाल के जवाब में दावा किया कि सूरत-बिलीमोरा (48 किलोमीटर) खंड पर दिसंबर 2026 में बुलेट ट्रेन का ट्रायल शुरू हो जाएगा।

अग्रिहोत्री ने बताया कि बुलेट ट्रेन परियोजना में वर्तमान में 20 हजार लोग नौकरी कर रहे हैं। जल्द एक लाख लोग इस परियोजना में नौकरी करेंगे। उन्होंने बताया कि मेक इन इंडिया के तहत सभी परियोजनाओं के टेके भारतीय कंपनियों को दिए गए हैं। नर्मदा ब्रिज, माही ब्रिज, ताप्ती ब्रिज व साबरमती ब्रिज पर वेल फाउंडेशन पर काम चल रहा है। इसके अलावा वापी-साबरमती तक सभी आठ बुलेट ट्रेन स्टेशनों पर निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में हैं। सतीश अग्रिहोत्री ने बताया कि जापान की तकनीकी, रोलिंग स्टॉक व सिग्नल सिस्टम होने के कारण बुलेट ट्रेन कभी भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगी। इस तकनीक को क्रैश एवॉयडेंस सिस्टम कहा जाता है।

पीएम मोदी ने दी बधाई तो शहबाज शरीफ ने कहा- थैंक्स, फिर अलापने लगे कश्मीर राग

नई दिल्ली, 12 अप्रैल (एजेन्सी)। एक तरफ भारत पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सत्ता हाथ में आते ही कश्मीर राग अलापने लगे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी की बधाई पर प्रतिक्रिया देते हुए भी उन्होंने कश्मीर की बात कर दी। शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा और फिर बोले, जो विवाद बचे हैं उनका शांतिपूर्ण समाधान निकलना चाहिए। जम्मू-कश्मीर विवाद को छोड़ा नहीं जा सकता।

बता दें कि सत्ता हाथ में आने से पहले ही वह अपना रंग दिखाते लगे थे। इसके बाद प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को संदेश देते हुए कहा था कि कश्मीर मुझे का समाधान कश्मीरी लोगों की इच्छा के मुताबिक किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी पूर्ववर्ती सरकार को भी कहे हुए कहा कि जब जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटया गया तो वह कुछ नहीं कर पाई।

बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी शरीफ को बधाई पत्र भी भेज सकते हैं। इसमें दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने पर जोर भी दिया जा सकता है। हालांकि अभी दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत को लेकर भी कोई फैसला नहीं लिया गया है।

बता दें कि पाकिस्तान में बड़े सियासी घमासान के बाद शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन गए हैं। इमरान खान को बीच कार्यकाल में ही इस्तीफा देना पड़ा। इससे पहले इमरान खान ने राष्ट्रपति से सिफारिश करके संसद भंग करवा दी थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा संसद बहाल कर दी। ऐसे में संसद में संख्या कम होने की वजह से इमरान खान को कुर्सी छोड़नी पड़ी।

राज ठाकरे का सरकार को अल्टीमेटम, '3 मई तक बंद कर दें मस्जिदों में लाउडस्पीकर'



मुंबई, 12 अप्रैल (एजेन्सी)। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने मंगलवार को राज्य सरकार को फ़िर से चेतावनी देते हुए कहा है कि वह मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटव दे। इस बार उन्होंने ठाकरे सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि उन्हें 3 मई तक मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद कर देना चाहिए। ठाकरे ने इस मुद्दे को एक सामाजिक मुद्दा बताया और कहा कि वह इस विषय पर पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने शिवसेना सरकार को यह कहते हुए चुनौती दी वह 'जो करना चाहे कर लें' लेकिन वे पीछे नहीं हटेंगे। मनसे प्रमुख ने कहा, 'मस्जिदों में लाउडस्पीकर 3 मई तक बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो हम स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। यह एक सामाजिक मुद्दा है, धार्मिक नहीं। मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूँ, हम इस विषय पर पीछे नहीं हटेंगे, आपको जो करना है कीजिए।

हाल ही में महाराष्ट्र में गरमाए लाउडस्पीकर विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री अर्जीत पवार

ने कहा था कि राज्य सरकार अदालत के आदेश पर चर्चा करेगी और इस बारे में गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल से बात करेगी। इस पर राज ठाकरे ने पवार को नास्तिक कहा, जो 'किसी धर्म को नहीं मानते।' इससे पहले शिवसेना नेता संजय राजत ने भी कहा था कि अजान के वास्ते लाउडस्पीकर पर डेसिबल स्तर बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भी नोटिस दिया है।

इस मुद्दे पर बहस तब छिड़ गई जब राज ठाकरे ने राज्य सरकार से मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए कहा और 'मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाने और हनुमान चालीसा बजाने' की चेतावनी दी।

उन्होंने कहा, 'मैं नमाज के खिलाफ नहीं हूँ, आप अपने घर पर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन सरकार को मस्जिद के लाउडस्पीकरों को हटाने का फैसला लेना चाहिए। मैं अभी चेतावनी दे रहा हूँ। इसके अलावा, राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुंबई के मुस्लिम इलाकों में मस्जिदों पर छपा मारने की भी अपील की और कहा कि वहां रहने वाले लोग 'पाकिस्तानी समर्थक' हैं।

आसनसोल में पुलिस ने मीडियाकर्मियों की रिपोर्टिंग करने से रोका

कोलकाता, 12 अप्रैल (एजेन्सी)। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के भीतर राज्य पुलिस द्वारा फ्री मीडिया मूवमेंट (पत्रकारों की ओर से स्वतंत्र रिपोर्टिंग) को रोकने की घटना पर आपत्ति जताई, जहां मंगलवार को उपचुनाव रहे हैं।

मीडियाकर्मियों से इस संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), पश्चिम बंगाल के कार्यालय ने हस्तक्षेप किया और राज्य पुलिस ने मीडिया मूवमेंट पर प्रतिबंध वापस ले लिया। आसनसोल लोकसभा के तहत आने वाले बाराबनी में मीडियाकर्मियों के एक समूह को कुछ समय तक स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

मंगलवार की सुबह आसनसोल से भाजपा प्रत्याशी अग्रिमित्र पॉल के बाराबनी के एक विशेष मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद तृणमूल कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच तनाव और झड़प हो गई। पॉल के वाहन में तोड़फोड़ की गई और उनका अंगरक्षक घायल हो गया। स्थानीय तृणमूल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पॉल कुख्यात असामाजिक तत्वों के साथ मतदान

केंद्र पर आए थे। जैसे ही पॉल बूथ के लिए रवाना हुए, मीडियाकर्मियों, चुनाव आयोग द्वारा जारी वैध चुनाव कवरेज पास के साथ, उनके वाहन का पीछा करने लगे। लेकिन जब वे बाराबनी में एक चौराहे पर पहुंचे, तो पॉल और मीडियाकर्मियों को एक विशाल पुलिस दल ने रोक दिया और एक पुलिस अधिकारी ने उनसे कहा कि एक आधिकारिक आदेश के बाद उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, उक्त पुलिस अधिकारी यह निर्दिष्ट नहीं कर सका कि यह आदेश ईसीआई या जिला मजिस्ट्रेट की ओर से आया है या किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की ओर से आया है। पुलिस अधिकारी कथित आदेश की कोई प्रति दिखाने में भी असमर्थ रहे।

पॉल की पुलिस अधिकारी से तीखी नोकझोंक हुई। भाजपा उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि मीडियाकर्मियों को प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि वे राज्य की सत्ताधारी पार्टी द्वारा चुनावी कदाचार का प्रसारण एवं रिपोर्टिंग कर रहे थे। इस बीच, मीडिया घरानों ने पश्चिम बंगाल के सीईओ के कार्यालय से संपर्क किया कि क्या मीडिया कार्यालयों को प्रतिबंधित करने के लिए चुनाव आयोग से

कोई आदेश दिया गया था। पश्चिम बंगाल कार्यालय के सीईओ ने स्पष्ट रूप से कहा कि ईसीआई से ऐसा कोई आदेश नहीं था और उन्होंने आसनसोल के लिए ईसीआई द्वारा नियुक्त अपने पर्यवेक्षकों और अधिकारियों से तुरंत संपर्क किया। ईसीआई के हस्तक्षेप के कुछ मिनट बाद, एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर आया और इसके बाद वहां तैनात पुलिस दल को वापस बुला लिया गया। उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा कि वे अपने कवरेज असाइनमेंट के साथ स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। लेकिन तब तक करीब 40 मिनट बीत चुके थे और इस दौरान मीडियाकर्मियों वहीं फंसे रहे और वह स्वतंत्र रूप से अपना काम नहीं कर पाए।

तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने घटना को कमतर आंकने की कोशिश करते हुए दावा किया कि यह पूरी घटना किसी गलतफहमी के कारण हुई।

सुबह 11 बजे तक आसनसोल लोकसभा और बालीगंज विधानसभा दोनों के लिए मतदान तुलनात्मक रूप से कम रहा। आसनसोल में मतदान का प्रतिशत 27 रहा जबकि बालीगंज में 16 प्रतिशत मतदान हुआ।

कंप्यूटर वायरस भी होंगे हाइब्रिड वारफेयर का हिस्सा, बिना पहली गोली चले हो जाएगा बहुत कुछ : वायुसेना चीफ

नई दिल्ली, 12 अप्रैल (एजेन्सी)। भारतीय वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी ने मंगलवार को कहा कि भविष्य के युद्ध की प्रकृति हाइब्रिड होने की संभावना है। इसमें आर्थिक प्रतिबंध, सूचना अवरोध, कंप्यूटर वायरस और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए) की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में अपने भाषण में एयर चीफ मार्शल ने कहा, 'साइबर और सूचना' युद्धक्षेत्र को आकार देने के आधुनिक उपकरण बन गए हैं। उन्होंने कहा कि सूचना के क्षेत्र में अच्छी तरह से गढ़ा गया विमर्श शत्रु को प्रभावित करेगा और इसके विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं।

वायुसेना के प्रमुख ने कहा कि लोग एक-दूसरे से आपस में बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं, ऐसे में हमारे नेटवर्क पर साइबर हमला कमान और नियंत्रण संरचनाओं को पंगु बना सकता है। उन्होंने कहा कि अगली जंग में दुश्मन शायद एक देश या संगठन न हो। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारत को शायद यह कभी



पता न चल पाए कि उसके कंप्यूटरों पर हमला करने वाले कौन लोग हैं और यह हमला कब तथा कहां से होगा। चौधरी ने कहा कि भविष्य में भारत पर सभी मोर्चों पर हमला किया जा सकता है, जिसमें आर्थिक प्रतिबंध से लेकर राजनयिक तौर पर अलग-थलग किए जाने और सैन्य गतिरोध से लेकर कंप्यूटरों पर हमला कर सूचना को अवरुद्ध करना तक शामिल है। उनके मुताबिक, यह सबकुछ पहली गोली चलने और पहले विमान के सीमा पार करने से पूर्व ही हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा, 'हम जिन हथियारों को देख रहे हैं वे एक छोटे कंप्यूटर वायरस से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल तक होंगे।' गौरतलब है कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी कई बार हाइब्रिड वारफेयर का जिक्र कर चुके हैं। यही नहीं वह अक्सर नई शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए 'डाई मोर्चे' के युद्ध की भी बात करते थे। 'डाई मोर्चे' के युद्ध से उनका अर्थ चीन, पाकिस्तान और देश के अंदर ही परसेप्शन वॉर से था।

यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में राम मंदिर की स्थापना से तनाव, लेफ्ट संगठनों का विरोध

हैदराबाद, 12 अप्रैल (एजेन्सी)। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में पत्थरों के ढांचे के बीच राम मंदिर बनाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राम नवमी के दिन उस जगह पर भगवान राम की फोटो रख उसे राम मंदिर घोषित कर दिया जिसका यूनिवर्सिटी के कई छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये यूनिवर्सिटी का भगवाकरण करने की कोशिश है। अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एसएसए) और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) पर यूनिवर्सिटी के गैर हिंदू छात्रों को मंदिर के जरिए बिना वजह भड़काने का आरोप लगाया है। वहीं एबीवीपी की तरफ से भी इस मामले पर बयान आया है।

एबीवीपी ने आधिकारिक तौर पर इस मामले से खुद को दूर रखते हुए कहा है कि ये छात्रों की अपनी धार्मिक आजादी है। जानकारी के मुताबिक रविवार को रामनवमी के दिन मौजूद हॉस्टल एक और चीफ वार्डन ऑफिस के पास मौजूद चट्टान के पास छात्रों ने भगवा रंग से उस जगह को रंग दिया और वहीं पेड़ के पास भगवान राम की फोटो स्थापित कर दी और कुछ भगवा रंग के झंडे गाड़ दिए। उस चट्टान पर कुछ छात्रों ने ओम और स्वस्तिक के निशान भी बना दिए। राम नवमी के दिन छात्रों ने यहीं बैठकर पूजा की और उस जगह को राम मंदिर के तौर पर स्थापित कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद स्टूडेंट्स यूनियन ने यूनिवर्सिटी

प्रशासन से कहा है कि वो यूनिवर्सिटी के भीतर किसी भी तरह के स्थाई धार्मिक प्रतीक को बनाने के खिलाफ आदेश जारी करें। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के प्रिंसिपल अशोक नंजन ने कहा कि- हमने अपनी आपत्ति यूनिवर्सिटी प्रशासन और वाइस चांसलर को दर्ज करा दी है। हमने उनसे अपील की है कि वो उस जगह पर फोटो हटकर व्हाइट वॉश करा दें। हालांकि दो दिन बाद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यूनिवर्सिटी की प्रवक्ता प्रोफेसर कंचन मलिक ने इस मामले में कहा है जब प्रशासन की तरफ से हमें इस मामले पर नोटिस मिलेगा तब हम कार्रवाई करेंगे।

वैष्णों देवी में मिलेगी कटरा से अर्धकुआरी तक रोपवे की सुविधा

कटरा, 12 अप्रैल (एजेन्सी)। माता वैष्णों देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी है। जम्मू-कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंगलवार को हाल में चुने गई श्री माता वैष्णों देवी श्राइन बोर्ड की बैठक में हिस्सा लिया और कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। आने वाले दिनों में माता वैष्णों देवी के दर्शन करने आने वाले भक्तों को कई सुविधाएं देने को मिलेंगी। मनोज सिन्हा ने कहा कि वैष्णों देवी में कई आधुनिक सुविधाएं जैसे स्काई वॉक, नया दुर्गा भवन, आध्यात्मिक थीम पार्क, रेडियो फ्रीक्वेंसी

आइडेंटिफिकेशन के साथ-साथ कटरा से अर्धकुआरी तक रोपवे की सुविधा मिलेगी। मनोज सिन्हा ने कहा कि हर साल देश-विदेश से माता वैष्णों देवी के दर्शन करने आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मनोज सिन्हा ने माता वैष्णों देवी मंदिर से जुड़े सभी प्रोजेक्ट का रिव्यू किया और नए दुर्गा भवन को जल्द से जल्द बनाने का निर्देश दिया। भवन पर भीड़ जमा होने से रोकने के लिए 9.89 करोड़ की लागत से यात्रा यूनिक मैनेजमेंट (स्काईवॉक) बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की

कुल लंबाई 160 से 170 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर होगी जिसमें दो रेसक्यू एरिया भी शामिल होंगे। पैसेंजर रोपवे के प्रोजेक्ट को मंजूरी देते हुए बोर्ड ने रोपवे कंपनियों के सीईओ से कहा है कि वो सुनिश्चित करें कि यात्रियों की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। इसके अलावा बोर्ड ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्राइन बोर्ड की सारी कमाई श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान से ही चलती है और उसी से विकास कार्य भी किए जाते हैं बोर्ड ने कॉरपोरेट डोनेशन पॉलिसी को भी स्वीकार कर लिया है।

मजिस्ट्रेट को एससीएसटी एक्ट में अर्जी पर कार्यवाही का अधिकार नहीं : हाईकोर्ट

प्रयागराज, 12 अप्रैल (एजेन्सी)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के प्रार्थना पत्र पर मजिस्ट्रेट को एससीएसटी एक्ट के तहत अपराध पर कार्रवाई का अधिकार नहीं है। शिकायतकर्ता एसपी से भी शिकायत कर सकता है। एक्ट के नियम 5(1) के तहत विशेष न्यायालय को भी शिकायत को परिवार मानकर उसपर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने सोनभद्र की सोनी देवी सहित विभिन्न जिलों की छह याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने मजिस्ट्रेट

या विशेष न्यायालय ने इस्तागासा मानकर कार्यवाही करने के आदेशों को विधि के विपरीत करार देते हुए रद्द कर दिया है। साथ ही शिकायतकर्ता को संबंधित एसओ से शिकायत कर एफआईआर दर्ज कराने को कहा है। शिकायतकर्ता एसपी से भी शिकायत कर सकता है। ऐसे मामले में सीधे विशेष न्यायालय को अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। याचिकाओं में कहा गया था कि मजिस्ट्रेट को एससीएसटी एक्ट में रखते हुए कि श्राइन बोर्ड की सारी कमाई श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान से ही चलती है और उसी से विकास कार्य भी किए जाते हैं बोर्ड ने कॉरपोरेट डोनेशन पॉलिसी को भी स्वीकार कर लिया है।



शिकायतकर्ता की एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो मजिस्ट्रेट अदालत में अर्जी दी गई, जिन पर अपराधिक केस दर्ज कर कार्यवाही की गई। याचिकाओं में ऐसे आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा, विशेष कानून के कारण सीआरपीसी की धारा 190 के तहत मजिस्ट्रेट को मिले अधिकार स्वयं समाप्त हो जाएंगे और विशेष कानून के प्रावधान लागू होंगे।

महबूबा मुफ्ती घर में नजरबंद



श्रीनगर, 12 अप्रैल (एजेन्सी)। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को अर्नतनाग जिले में जाने से रोकने के लिए जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर शहर में उन्हें नजरबंद कर दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी है।

मुफ्ती ने आरोप लगाया कि वह शोपियां जिले में कश्मीरी पंडित के परिवार से मिलने का इरादा रखती थीं, जिन पर 6 अप्रैल को उनके पौत्रक गांव में आतंकवादियों ने हमला किया था। उन्होंने नजरबंद करने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, महबूबा

मुफ्ती ने अपने टिवटर पेज पर कहा, 'आज मुझे घर में नजरबंद रखा गया क्योंकि मैं शोपियां में हमले का शिकार हुए कश्मीरी पंडित के परिवार से मिलना चाहती थी। भारत सरकार जानबूझकर कश्मीरी मुख्यधारा और मुसलमानों के बारे में फेक न्यूज फैलाती है। पंडितों के पलायन के लिए जिम्मेदार हैं और नहीं चाहते कि इस फर्जी विभाजनकारी नैरेटिव का पदार्पाश हो।'

अधिकारियों ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को सुरक्षा कारणों से यात्रा करने से रोका गया था।

लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की नीतीश सरकार से मांग, शराब की तर्ज पर बंद हो गुटखा



पटना, 12 अप्रैल (का.सं.)। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे व विधायक तेज प्रताप यादव अपनी वेशभूषा व अनूठे बयानों को लेकर सदैव चर्चा में रहते हैं। इस बार तेज प्रताप यादव एक नई मुहिम से जुड़े हैं। आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर किस मुहिम से लालू के लाल जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि तेज प्रताप यादव अब बिहार में गुटखा (रजनीगंधा तुलसी) को बंद करवाने की मुहिम से जुड़ गए हैं।

तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। अपने ट्वीट में तेज प्रताप ने लिखा है कि नीतीश चचा जी ये दारू बंदी बहुत हुई... अब जरा रजनीगंधा तुलसी भी बंद करवाये... कही आप भी तो मुँह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया वाली बात पर यकीन नही कर रहे। मुहिम - बंद करो रजनीगंधा तुलसी।

मंत्री शर्मा ने किया खाम्दोंग ब्लॉक डेवलपमेंट सोसाइटी का उद्घाटन



अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 12 अप्रैल। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, आरडीडी के अंतर्गत खाम्दोंग प्रशासनिक केंद्र में मंत्री डॉ. एमके शर्मा ने खाम्दोंग ब्लॉक डेवलपमेंट सोसाइटी का उद्घाटन किया।

उक्त उद्घाटन कार्यक्रम में सीईओ सह विशेष सचिव एसआरएलएम, डिप्टी सीईओ सह उप सचिव एसआरएलएम, प्रोजेक्ट मैनेजर, जिला पंचायत, पंचायत अध्यक्ष, खाम्दोंग बीडीओ एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

जिलाधिकारी ने की

पाकिम, एडीसी विकास, एसएसपी, एसडीएम, डीपीओ के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बताया गया कि बैठक सफल रही और इसमें आपातकाल के समय सभी विभागों ने हर समय तैयार रहने और आपसी समन्वय पर सहमत हुए।

बैठक के बाद एडीसी पाकिम, एसडीएम पाकिम, डीपीओ, आरओ पाकिम तथा एएचआईडीसीएल ने पाकिम-रानीपुल सड़क के खतरनाक व संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया।

दुनिया का पेट भरने को तैयार है भारत, बस डब्ल्यूटीओ की मिल जाए मंजूरी : पीएम मोदी

नई दिल्ली, 12 अप्रैल (एजेन्सी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अपनी बातचीत के दौरान, उन्होंने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की अनुमति मिलने पर दुनिया को भारत के खाद्य भंडार की आपूर्ति करने की पेशकश की। पीएम मोदी ने वीडियो लिंक के माध्यम से गुजरात के अदलज में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास और शिक्षा परिसर का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि युद्ध (यूक्रेन में) के कारण दुनिया के विभिन्न हिस्सों में खाद्य भंडार घट रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'वैश्विक खाद्य भंडार (यूक्रेन में) युद्ध के कारण घट रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत के दौरान मैंने कहा कि अगर, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) कुछ छूट देता है, तो हम दुनिया को भारतीय खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना शुरू कर सकते हैं।'

उन्होंने कहा, आज दुनिया एक अनिश्चित स्थिति का सामना कर रही है क्योंकि किसी को वह नहीं मिल रहा है जो वे चाहते हैं। पेट्रोल, तेल और उर्वरक खरीदना मुश्किल है क्योंकि सभी दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। इसके (रूस-यूक्रेन) युद्ध शुरू होने के बाद से हर कोई अपने स्टॉक को सुरक्षित करना चाहता है। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया अब एक नई समस्या का सामना कर रही है; दुनिया का अन्न भंडार खाली हो रहा है, मैं अमेरिकी राष्ट्रपति से बात कर रहा था, और उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। मैंने सुझाव दिया कि अगर विश्व व्यापार संगठन अनुमति देता है, तो भारत कल से दुनिया को खाद्य भंडार की आपूर्ति करने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा, हमारे पास पहले से ही अपने लोगों के लिए पर्याप्त भोजन है लेकिन हमारे किसानों ने दुनिया को खिलाने की व्यवस्था की



है। हालांकि, हमें दुनिया के कानूनों के अनुसार काम करना है, इसलिए मुझे नहीं पता कि विश्व व्यापार संगठन कब अनुमति देगा ताकि हम दुनिया को भोजन की आपूर्ति कर सकते हैं।

जहां भी कमियां नजर आएंगी, उसे दूर करेंगे : सीएम नीतीश

पटना, 12 अप्रैल (का.सं.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पिछले 16 सालों से हम बिहार की सेवा कर रहे हैं। बिहार में काफी काम हुए हैं। हर जगह जाकर हम स्वयं सबकुछ देखते ही रहते हैं। जहां भी कमियां नजर आती हैं, उसमें सुधार करते हैं। आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को राजगीर विधानसभा क्षेत्र (पुराना) के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया और अपने पुराने साथियों से मिलकर हाल-चाल जाना। उन्होंने कहा कि आप लोगों का सहयोग एवं समर्थन मुझे हमेशा मिलता रहा है, उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। हम आपको आश्चर्य करते हैं कि जो भी हमसे संभव होगा, उसे हम करते रहेंगे। आज बिहार आगे बढ़ रहा है, इसे और आगे बढ़ाना है। आपके सुझाव पर भी



हम काम करेंगे। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग समाज में अच्छा माहौल बनाकर रखिये। सीएम नीतीश ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पर हमने मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भी शुरू करवाया है। इस बार मेरी इच्छा थी एक बार हम सब जगहों पर फिर से जायेंगे। इसी सिलसिले में

आपके बीच भी आने का मौका मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गिरियक प्रखंड के पावापुरी (विरायतन प्रशिक्षण महाविद्यालय का प्रांगण), सिलाव प्रखंड के नानंद एवं मेन रोड हाई स्कूल सिलाव तथा राजगीर प्रखंड के बेलदार बिगाह (उच्च विद्यालय प्रांगण) में

अपने पुराने साथियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री का स्वागत सभी ने फूलों की बड़ी माला, प्रतीक चिह्न एवं अंगवस्त्र भेंटकर किया। मुख्यमंत्री ने पावापुरी स्थित जल मंदिर में पूजा-अर्चना कर राज्य की सुख, शांति, समृद्धि एवं लोगों में आपसी सौहार्द कायम रहने की कामना की।

सीएम नीतीश की सुरक्षा 16 दिन के भीतर फिर हुई चूक, सिरफिरे युवक ने सभा में पटाखा फोड़ा

नालंदा, 12 अप्रैल (नि.सं.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंवाद यात्रा के दौरान मंगलवार को सिलाव पहुंचे। गांधी हाईस्कूल के पास बनाये गये पंडाल में सभा थी। मुख्यमंत्री सभास्थल पर पंडाल में घूम-घूमकर लोगों से आवेदन ले रहे थे। इसी दौरान सीएम से मात्र पांच फीट की दूरी पर एक सिरफिरे युवक ने पटाखा जलाकर फेंका। हालांकि, इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस का भी कहना है कि पटाखा फोड़ा गया है। यह दूसरी घटना है जब सीएम की सुरक्षा में चूक सामने आई है। इस घटना से 16 दिन पहले 27 मार्च को बख्तियारपुर में एक युवक ने सीएम पर हमले की कोशिश की थी।

पटाखे की आवाज से वहां अफरातफरी मच गई। सुरक्षाकर्मियों ने सीएम को घेर लिया। स्थानीय पुलिस ने युवक को दबोच लिया। उसके पास से एक और पटाखा बम, माचिस, आधार कार्ड व अन्य सामान बरामद किये गये। गिरफ्तार युवक की पहचान इस्लामपुर बाजार के सत्याग्रज मोहल्ला निवासी स्व. प्रमोद कुमार के 22 वर्षीय पुत्र शुभम आदित्य के रूप में की गई है। लोगों की मानें तो युवक सालों से मानसिक रूप से बीमार है।

प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो सभास्थल में गैलरी बनी थी। गैलरी के दोनों ओर लोग कुर्सियों पर बैठे थे। गैलरी में घूमकर सीएम लोगों से हालचाल पूछते हुए आवेदन ले रहे थे। गिरफ्तार युवक गैलरी में लगी बांस की बैरिकेडिंग के बाद दूसरी कुर्सी पर चुपचाप बैठा था। जैसे ही सीएम नजदीक

पहुंचे, उसने पटाखा फोड़ दिया। इसके कारण जमीन पर बिछाया गया कारपेट करीब इंच की गोलाई में जल गया। पटाखे की आवाज सुनकर लोग भागने लगे।

युवक की गिरफ्तारी के बाद सीएम ने खुद मोर्चा संभाला और लोगों से शांत रहने की अपील की। इसके बाद भी उन्होंने कई लोगों के आवेदन लिये। आवेदन लेने के बाद वे मंच पर पहुंचे और बिना माइक के ही लोगों को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से मिल-जुलकर रहने की अपील की।

इस्लामपुर बाजार में सभी लोग युवक को जानते हैं। इसके कई कारण हैं। बाजार के राजगीर रोड में सत्यम ट्रेडर्स के नाम से छड़-गिट्टी की दुकान है। हालांकि, दुकान उसके दो बड़े भाई कुणाल और आदित्य संभालते हैं। वह तीन

भाइयों में सबसे छोट है। युवक सालों से असामान्य हरकत करता रहा है। कई बार घर में बिना बताये भाग जाता था। एक बार लाखों के जेवर व नकद रुपये लेकर घर से भागा था। स्थानीय लोगों की मानें तो उसकी हरकतों के कारण ही पिता की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। युवक के पास एक स्कोर्पियो है, उसे वह भाड़े पर चलाता है। युवक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

थाने में डीएसपी उससे पूछताछ कर रहे हैं। इधर, सिलाव पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में युवक के परिजन से पूछताछ करने के लिए इस्लामपुर थाना पहुंची। वहां पुलिस युवक के परिजनों से पूछताछ कर रही है। सिलाव थानाध्यक्ष पवन कुमार ने बताया कि युवक से पूछताछ जारी है।

पंजाब के नौकरशाहों से मीटिंग के बाद केजरीवाल ने भगवंत मान को बुलाया, मुफ्त बिजली के लिए करना होगा इंतजार

नई दिल्ली, 12 अप्रैल (एजेन्सी)। आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब में सत्ता में आने पर हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया गया था। लेकिन पंजाब के लोगों को फिलहाल इसके लिए महीने भर का इंतजार करना होगा। 300 यूनिट मुफ्त बिजली की स्कीम पर फिलहाल विचार चल रहा है और इसके तौर-तरीकों को फाइनल टच देने के लिए अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को दिल्ली बुलाया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के नौकरशाहों और संबंधित अधिकारियों से भी इस मसले पर बात की थी। इसके बाद अब मान को बुलाया गया है। जिससे माना जा रहा है कि स्कीम को लागू करने में कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, जिसे दूर करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग्स की हैं।

अरविंद केजरीवाल के दफतर से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली की स्कीम का जल्दी ही ऐलान किया जाएगा। इससे पहले आज दोपहर 3 बजे अरविंद केजरीवाल के घर पर भगवंत मान पहुंचने वाले हैं और दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। केजरीवाल के ऑफिस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, 'पंजाब में आप की सरकार को बने हुए करीब एक महीना हो गया है। केजरीवाल इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि पंजाब के लोगों को जल्द ही मुफ्त बिजली का लाभ मिलना चाहिए और इसका ऐलान जल्द ही किया जाएगा। फिलहाल इस बात की चर्चा हो रही है कि इसका खर्च पंजाब का बिजली विभाग कैसे उठाएगा और कैसे इसके बेजा इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी।'

भगवंत मान ने 16 मार्च को



सीएम पद की शपथ ली थी। बता दें कि चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे, उनमें सबसे अहम मुफ्त बिजली का ही था। बीते साल जून में अरविंद केजरीवाल ने आप की पहली गारंटी देते हुए कहा था कि हम सत्ता में आते ही लोगों को मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली है और अब इस वादे के पूरा होने का इंतजार लोग कर रहे हैं। गौरतलब है कि

सूबे की 117 सीटों में से आप को कुल 92 सीटों पर जीत मिली है, जो असाधारण बहुमत है।

गौरतलब है कि गरीबों के लिए पंजाब में पहले से ही मुफ्त बिजली की स्कीम चल रही है, जिसकी शुरुआत 2016 में कांग्रेस सरकार की ओर से की गई थी। फिलहाल पंजाब में अनुसूचित जाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लोगों और गरीबी रेखा से नीचे गुजारा करने वाले परिवारों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है।

दिल्ली में आने वाली है कोरोना की चौथी लहर? केजरीवाल बोले- स्थिति पर सरकार की पैनी नजर, अभी घबराने की जरूरत नहीं



राजेश अलख

नई दिल्ली, 12 अप्रैल। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की संक्रमण दर एक बार फिर बढ़ने लगी है। हालात देखकर जहां चौथी लहर को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं, वहीं सरकार भी सतर्क हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार राजधानी में कोविड-19 की स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है और फिलहाल घबराने की कोई बड़ी वजह नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सोमवार को कोविड महामारी की संक्रमण दर बढ़कर 2.70 फीसदी पहुंच गई जो पिछले दो महीनों में सबसे ज्यादा है। इससे राजधानी में कोविड के फिर से फैलने को लेकर चिंता बढ़ गई है। दिल्ली में पांच फरवरी को संक्रमण दर 2.87 फीसदी थी।

केजरीवाल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि हम स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं। अभी घबराने की कोई बड़ी वजह नहीं

है। हम स्थिति के मुताबिक, सभी जरूरी कदम उठाएंगे।

इससे एक दिन पहले सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि दिल्ली सरकार कोविड की स्थिति पर नजर रख रही है और जब तक कोरोना वायरस के नए चिंताजनक वैरिएंट का पता नहीं चलता, तब तक फिफ्ट की कोई बात नहीं है। जैन ने कहा था कि दिल्ली में दैनिक मामले 100-200 के बीच आ रहे हैं। हम अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों पर नजर रख रहे हैं और इनकी संख्या कम हो रही है। फिलहाल संक्रमण दर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि दिल्ली में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 137 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 18,66,380 हो गई। राजधानी में संक्रमण दर में वृद्धि देखी गई है और यह बढ़कर 2.70 प्रतिशत हो गई है। हेल्थ बुलेटिन में कहा गया है कि मुक्तों की संख्या अब भी 26,157 है। चार अप्रैल को संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत थी, जो सोमवार तक बढ़कर 2.70 फीसदी हो गई।

NAGALAND STATE LOTTERIES	
Draw Time: 01:00 PM	
DEAR TEESTA MORNING	
Draw No:72 DrawDate on:12/04/22	
1st Prize ₹1 Crore/- 63G 16882	
Cons. Prize Rs.1000/- 16882 (REMAINING ALL SERIALS)	
2nd Prize ₹9000/-	
02048 10508 14668 27798 37739 44506 72773 75838 88856 89782	3rd Prize ₹450/-
1876 2488 2882 4108 4536 4726 5417 6165 6351 7472	4th Prize ₹250/-
0331 1280 4368 4490 5714 5888 6651 6905 7522 8903	5th Prize ₹120/-
0004 0257 0337 0414 0457 0495 0502 0503 0823 0868	
1006 1011 1039 1221 1269 1273 1294 1428 1560 1563	
1581 1659 1667 1743 1957 2196 2348 2444 2525 2561	
2848 2891 3034 3088 3106 3202 3208 3238 3253 3353	
3381 3474 3583 3603 3627 3681 3682 3811 4222 4669	
4818 4821 5012 5388 5412 5560 5572 5729 5887 5989	
6056 6076 6357 6486 6491 6525 6558 6560 6579 6657	
6780 7032 7084 7372 7375 7576 7599 7612 7614 7649	
7769 7779 7843 7887 7944 8035 8151 8237 8243 8380	
8553 8682 8868 8970 9136 9144 9471 9501 9530 9709	
ISSUED BY : THE DIRECTOR	
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND	
For Results, Please Visit : www.NagalandLotteries.com	
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE	

NAGALAND STATE LOTTERIES	
Draw Time: 08:00 PM	
DEAR PARROT EVENING	
Draw No:172 DrawDate on:12/04/22	
1st Prize ₹1 Crore/- 78G 35209	
Cons. Prize Rs.1000/- 35209 (REMAINING ALL SERIALS)	
2nd Prize ₹9000/-	
10351 32516 34376 63875 66778 69038 69168 78957 87245 89000	3rd Prize ₹450/-
0318 3271 3581 4308 4547 4768 5018 6561 7640 9636	4th Prize ₹250/-
1052 1354 2173 2913 2922 2940 3084 4445 7041 9226	5th Prize ₹120/-
0035 0150 0414 0437 0457 0484 0513 0800 0949 1088	
1101 1269 1309 1313 1396 1415 1428 1797 1804 1829	
2034 2240 2260 2305 2402 2509 2514 2945 3058 3153	
3261 3523 3535 3758 3879 3922 4013 4341 4356 4454	
4486 4496 4693 4850 5047 5093 5110 5138 5220 5244	
5317 5379 5535 5538 5580 5654 5666 5698 5779 6049	
6215 6218 6226 6274 6429 6737 6806 6953 7077 7083	
7180 7332 7408 7577 7604 7698 7950 7954 8122 8170	
8269 8287 8320 8508 8598 8705 8715 8808 8925 8967	
9006 9115 9174 9268 9286 9303 9595 9840 9932 9937	
ISSUED BY : THE DIRECTOR	
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND	
For Results, Please Visit : www.NagalandLotteries.com	
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE	

NAGALAND STATE LOTTERIES	
Draw Time: 06:00 PM	
DEAR MOON TUESDAY	
Draw No:72 DrawDate on:12/04/22	
1st Prize ₹1 Crore/- 89E 71668	
Cons. Prize Rs.1000/- 71668 (REMAINING ALL SERIALS)	
2nd Prize ₹9000/-	
05773 27185 43665 46816 48089 51529 58328 62012 92217 99274	3rd Prize ₹450/-
0343 0556 0714 1821 2388 3860 4816 5231 5880 8245	4th Prize ₹250/-
1974 2278 2324 2453 4096 5680 7756 8500 9096 9544	5th Prize ₹120/-
0153 0315 0580 0592 0718 0786 0936 0991 1134 1160	
1358 1425 1505 1576 1595 1640 1686 1965 1976 2050	
2136 2431 2476 2515 2543 2658 2692 2881 2885 2904	
2917 3283 3497 3541 3673 3753 3833 3892 4282 4337	
4373 4617 4776 4807 4919 4968 4990 5019 5251 5490	
5551 5652 5755 6010 6037 6090 6187 6226 6309 6318	
6365 6510 6534 6595 6613 6818 7027 7053 7086 7087	
7117 7135 7282 7364 7452 7479 7694 8038 8061 8108	
8360 8465 8917 8949 9010 9087 9147 9149 9152 9190	
9195 9248 9290 9312 9418 9635 9658 9714 9813 9952	
ISSUED BY : THE DIRECTOR	
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND	
For Results, Please Visit : www.NagalandLotteries.com	
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE	

मोदी-बाइडन वार्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के बीच हुई आभासी शिखर-वार्ता के गहरे निहितार्थ हैं। रियायती दर पर भारत को तेल बेचने के रूसी प्रस्ताव को लेकर एकाधिक अमेरिकी बयानों से भ्रम की स्थिति बन गई थी। पश्चिमी मीडिया का एक हिस्सा इन बयानों को अमेरिकी नाखुशी के रूप में पेश करने में जुटा था, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत-अमेरिकी 2+2 वार्ता के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में स्पष्ट कर दिया कि रूस से पेट्रो उत्पादों की खरीद के संदर्भ में भारत को लेकर अमेरिका को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूरोप जितना एक दोपहर में उससे तेल खरीदता है, भारत उतना महीने भर में भी आयात नहीं करता। वाशिंगटन को यह मानना पड़ा है कि भारत का तेल आयात मॉस्को पर आयद प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं है और यूक्रेन युद्ध के मामले में भारत अपनी भूमिका लेने के लिए आजाद है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया की बड़ी शक्तियां अब खुलकर आमने-सामने आ चुकी हैं और अमेरिका चाहता है कि रूस पर आर्थिक दबाव बनाए रखा जाए। इसलिए मॉस्को से पेट्रो उत्पादों के अलावा हथियार खरीद के नए समझौतों को लेकर भी उसने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। लेकिन वाशिंगटन को यह समझने की जरूरत है कि रूस के साथ भारत के दशकों पुराने सामरिक संबंध हैं और वह अपने हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। यूक्रेन मामले पर संयुक्त राष्ट्र की तमाम वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहकर भी भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह अपने कंधे का इस्तेमाल करने की इजाजत किसी को नहीं देगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख से भी वाशिंगटन को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारत वैश्विक शांति और अपने हितों के बीच संतुलन साधना जानता है। प्रधानमंत्री ने बातचीत के दौरान एक बार भी रूस का नाम नहीं लिया।

भारत को अपने पक्ष में करने की अमेरिकी रणनीति समझी जा सकती है। ये दोनों देश दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। फिर वाशिंगटन जानता है कि चीन पहले से मॉस्को के साथ है। उसके पास मजबूत आर्थिक व सैन्य ताकत के अलावा एक विशाल बाजार भी है, जिसका जवाब सिर्फ भारत हो सकता है। भारत और चीन के तनावपूर्ण संबंधों में भी वह अपने लिए संभावनाएं देख रहा है। चंद्र रोज पहले उसके उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह की अराजनयिक टिप्पणी इसी बात की तस्दीक करती है। अब वह भारत की ऊर्जा व सैन्य जरूरतों में अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है। यह सही है कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति परिस्थितियों से संचालित होती है, लेकिन नाजुक मौकों पर रूस के सहयोग को भारत कैसे भूल सकता है? वह भी उस अमेरिका के मुकाबले, जिसने तमाम सुबूतों के बावजूद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के मामले में भारतीय हितों की हमेशा अनेदखी की? इन सबके बावजूद प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के मासूम नागरिकों की हत्या की तीखी निंदा की है। और यह भारत का पुराना रुख है, वह किसी अमानवीय कृत्य की हिमायत नहीं कर सकता। निस्संदेह, भारत को भी अमेरिका के साथ और सहयोग की आवश्यकता है, पर वाशिंगटन को समझना होगा कि इकतरफा दबाव का दौर अब खत्म हो चुका है। यूरोप का रूस से जारी कारोबार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए परस्पर सम्मान और समझदारी से ही भारत-अमेरिकी संबंध भी एक नई ऊंचाई को छू सकेंगे।

संवादकीय पृष्ठ

आयुष्मान भारत ने बदली स्वास्थ्य देखभाल सेवा की तस्वीर

डॉ. आर.एस. शर्मा
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण

भारत के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य देखभाल को विश्व-स्तरीय बनाने के ध्येय से 2017 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) को अंगीकार किया था। इसे अंगीकार करते समय सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह उभरकर आया था कि किस तरह भारत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को तीव्रता से प्राप्त करे। भूत में भारत में स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति पर अंतर्दृष्टि डालने पर यह साफ-साफ दिख रहा था कि स्वास्थ्य देखभाल की लागत पर होने वाले खर्चों के कारण आम आदमी की क्रय शक्ति प्रभावित हो रही है, अतः इन खर्चों को कम करना भी एनएचपी के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल था। उपरोक्त कारणों की पुष्टिभूमि में ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री - जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जय) की परिकल्पना की गई ताकि स्वास्थ्य सेवा वितरण को समग्र दृष्टिकोण के साथ तीव्रता प्रदान की जा सके और देश के अंतिम जन की पहुंच किफायती एवं गुणवत्ता-युक्त स्वास्थ्य सेवाओं तक सुलभता से हो सके।

ऐसा नहीं है कि आयुष्मान भारत पीएम-जय स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में देश का पहला प्रयास था बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई), राज्यों की योजनाओं जैसे आंध्र प्रदेश में आरोग्यश्री, महाराष्ट्र में जीवनदायी योजना जैसी पूर्ववर्ती योजनाओं को भी भरपुर श्रेय दिया जाना चाहिए। वर्तमान में यह भी सच है कि एबी पीएम-जय ने स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन के क्षेत्र में बाकी तमाम हितधारकों को पीछे छोड़ते हुए एक बड़ा मुकाम हासिल किया है।

इसके विस्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मौजूदा समय में आयुष्मान भारत पीएम-जय राज्य स्वास्थ्य योजनाओं के साथ मिलकर 14 करोड़ से अधिक परिवारों (70 करोड़ व्यक्तियों) के लाभार्थी आधार को कवर कर रहा है। अभी तक इस योजना के तहत लगभग 18 करोड़ व्यक्तियों की पहचान कर उनका आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। वैश्विक महामारी

के बीच महज 3.6 वर्षों के अपने छोटे से क्रियावन्वयन काल में एबी पीएम-जय ने अस्पताल-भर्ती के साथ लगभग 3.28 करोड़ उपचार प्रदान किया है, जिसपर उपचार खर्च 37,600 करोड़ से ज्यादा का रहा है।

वर्तमान में जिस प्रकार से आयुष्मान भारत पीएम-जय अपनी उड़ान भर रहा है, यह माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण और कैबिनेट द्वारा संकल्पित बहुमुखी नीतिगत ढांचे का परिणाम है। आयुष्मान भारत पीएम-जय के पीछे के मार्गदर्शक सिद्धांतों को स्पष्ट करने वाले प्रमुख बिन्दुओं को निम्न रूपों में समझा जा सकता है:

एबी पीएम-जय की जब प्रारंभ हुआ था तब 1,393 उपचार पैकेज था लेकिन अब इसका विस्तार 1670 उपचार पैकेजों तक किया जा चुका है। इन पैकेजों में ऑन्कोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कांडिडोस्कुलर सर्जरी आदि जैसी विभिन्न चिकित्सा विशेषताओं के उपचार के लिए 5 लाख रुपये तक प्रति लाभार्थी परिवार को प्रति वर्ष कवर प्रदान किया जाता है।

अस्पताल में भर्ती होने और बाद के खर्चों का भी ख्याल इन पैकेजों में रखा गया है, इतना ही नहीं पोर्टेबिलिटी फीचर के माध्यम से देश के दूर-दराज के लाभार्थी भी देश के किसी भी कोने में जाकर आयुष्मान सूचीबद्ध अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल ले सकते हैं।

एबी पीएम-जय के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को उनके क्रियावन्वयन के तरीके, लाभार्थी डेटाबेस को चुनने और अस्पतालों का नेटवर्क बनाने में काफी लचीलापन प्रदान किया गया था। इसके अलावा, एनएचए ने मौजूदा राज्य आधारित योजनाओं के साथ भी तत्परता-पूर्वक अभिसरण किया। वर्तमान में, एबी पीएम-जय को 25 से अधिक राज्य-विशिष्ट स्वास्थ्य योजनाओं के साथ मिलकर लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त, देश भर के 600 से अधिक जिलों में जिला क्रियावन्वयन इकाइयां (डीआईयू) स्थापित की गई हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एबी

पीएम-जय की प्रशासनिक पहुँच लाभार्थी के घर तक हो सके।

सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के तहत कवर किए गए समाज के हाशिए के वर्गों के लिए योजना के लाभों का विस्तार करने हेतु नए सिरे से प्रोत्साहन दिया गया है। इसी तरह, एबी पीएम-जय ने लिंग-विशिष्ट समानता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रबुद्ध दृष्टिकोण अपनाया है। पूर्ववर्ती आरएसबीवाई योजना में परिवार के सदस्यों के ऊपरी सीमा पर केंप था, जिसके कारण घर के औरतों का उपचार नहीं हो पाता था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एबी पीएम-जय परिवार के सदस्यों की संख्या को कैंप नहीं किया गया है। जिसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। एनएचए आईटी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बनाए गए आयुष्मान कार्डों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 50 प्रतिशत और अधिकृत अस्पताल में भर्ती होने वालों में 47 प्रतिशत है।

पहले की योजनाओं को लागू करने में यह देखने को मिला था कि आईटी सिस्टम की एकरूपता नहीं होने के कारण वितरण प्रभावित होता था। इस समस्या को दूर करने के लिए एबी पीएम-जय के तहत, लाभार्थी की पहचान, लेन-देन प्रबंधन और अस्पताल के पैलल में सहायता के लिए एक अत्यधिक बहुमुखी प्रौद्योगिकी मंच को विकसित किया गया है। अपनी नवीनता एवं परिवर्तनात्मकता के कारण सम्मानित हो चुकी यह आईटी खल्लेटफॉर्म अब 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय है। इससे एनएच-एसएचए स्तर पर सक्ष-आधारित नीति निर्माण और जरूरी सुधार में सहायता मिलती रही है। आयुष्मान भारत पीएम-जय के तहत योजना के लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी ने योजना के लाभार्थियों के लिए इलाज की तलाश करने के रास्ते बढ़ा दिए हैं और साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में तृतीयक देखभाल सुविधाओं पर बोज़ कम कर दिया है। एबी पीएम-

जय के तहत, यह सुनिश्चित किया गया था कि सार्वजनिक अस्पतालों को उनकी सेवाओं के लिए समान रूप से और निजी अस्पतालों के समान दरों पर प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसने सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों को अनटइड फंड का एक पुल बनाने में भी मदद की है, जिसे बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों में स्थायी रूप से निवेश किया जा सकता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अस्पतालों की पूरक भूमिका यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रही है कि योजना का क्रियावन्वयन निर्बाध रूप से आगे बढ़े।

एनएचए का कार्यभार संभालने के बाद मैंने जिन प्रमुख गतिविधियों को हरी झंडी दिखाई, उनमें से एक है 'आपके द्वार आयुष्मान'। आपके द्वार आयुष्मान के तहत, फ्रंटलाइन हेल्थकेयर वर्कर्स, ग्राम पंचायत अधिकारियों और गांव-आधारित डिजिटल उद्यमियों के एक जमीनी नेटवर्क का उपयोग समुदायों में लाभार्थियों तक घर-घर पहुंचकर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए किया गया था। दिहाड़ी मजदूरों के लिए विशेष रात्रि शिविर लगाए गए। इन प्रयासों का का ही नतीजा है कि जनवरी 2021 से 4.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्डों के निर्माण हुआ, एनएचए आईटी सिस्टम द्वारा बनाए गए आयुष्मान कार्डों में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एनएचए नए जोश के साथ आपके द्वार आयुष्मान कार्ड ड्राइव को पुनः लॉन्च करने का रहा है। इस बार हम असम, बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

अंत में, मैं एबी पीएम-जय को सफलता के सोपान पर पहुंचाने में अथक परिश्रम करने के लिए एनएचए, एसएचए, डीआईयू, क्रियावन्वयन सहायता एजेंसियों, प्रधान मंत्री आरोग्य मित्र, फ्रंटलाइन हेल्थकेयर वर्कर्स, आयुष्मान कार्ड बनाने वाली एजेंसियां जैसे सीएससी/यूटीआईआईटीएसएल से मिलकर बने पूरे आयुष्मान भारत पीएम-जय इकोसिस्टम को भी इसका श्रेय देना चाहूंगा। हालांकि, इस योजना को अपनी पूरी क्षमता का दोहन करने में मदद करने के लिए एनए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

बहुत कुछ कह गया परिणाम

धीरेंद्र कुमार

बिहार की राजनीति में एक नई करवट लेने की सुगबुगाहट होने की आहट मिल रही है।

विधान परिषद के हालिया संपन्न चुनाव परिणाम ने अपरोक्ष रूप से राज्य की सियासत में नये तरह के संकेत जरूर दिए हैं। बिहार की राजनीति की दो ताकतवर जातियां एक साथ आने को अब तैयार दिख रही हैं। 175 सदस्यीय बिहार विधान परिषद के 24 सीटों के लिए हुए मतदान का परिणाम सामने है। 13 सीट जीतने के बाद बाजी भाजपा-जद (यू) गठबंधन यानी एनडीए के हाथ लगी। वहीं 06 सीट जीतने के बावजूद बाजीगर कहलाने का हक लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद को मिला है। आम लोगों के बीच धारणा है कि इस चुनाव को जनता का मत/मिजाज ना समझा जाए। अलबत्ता मैं इस परंपरागत धारणा से सहमत नहीं हूँ और इसे सिरे से खारिज करता हूँ। ये सही है कि इस चुनाव से सरकार को सेहत पर तुरंत असर नहीं पड़ने वाला। फिर भी, इसकी गूँज देर तक और दूर तलक सुनी जाएगी।

इस विधानपरिषद चुनाव के मतदाताओं की कैटेगरी को देखिए। कौन हैं ये लोग? ये वो लोग हैं, जो भारतीय लोकतंत्र की क्रमतालिका में जनता से सीधे चुने गए हैं। इनमें वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, जिला पाषर्द, एमएलए, एमएलसी, सांसद शामिल हैं। अब जरा शहर से लेकर गांव तक की राजनीतिक फिजां पर गौर कीजिए। वो कौन लोग होते हैं जो किसी भी पार्टी के पक्ष में या विरोध में माहौल बनाते हैं। ये वो ही लोग हैं जो त्रिस्तरीय पंचायती राज में चुनाव जीत कर आए हैं।

जातिगत राजनीति में जकड़ी बिहार की भूमि पर वो कौन सी जातियां हैं जो बिहार में प्रभावी हैं। जवाब है सवणों में भूमिहार, पिछड़ों में यादव और दलितों में पासवान। कतिपय सामाजिक-राजनीतिक कारणों से कालांतर से ही बिहार में भूमिहार और यादव एक-दूसरे के खिलाफ रहे। इस दूरी को 24 विधानपरिषद सीटों पर हुए चुनाव ने बहुत हद तक पाट दिया, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इस चुनाव में भाग्य आजमा रहे उम्मीदवारों के सामाजिक चरित्र को देखने पर कुछ संकेत चौंकारने वाले हैं। राष्ट्रीय जनता दल जिसकी पहचान यादव और मुस्लिमों की पार्टी के रूप में है। इसके 10 यादव उम्मीदवार में से 09 चुनाव हार गए। एक भी मुसलमान कैंडिडेट किसी भी खेमे से जीत नहीं दर्ज कर सका। नीतीश कुमार को कोर वोटर जिसका वो अपना होने का दावा करते हैं, कुर्मी और कुशवाहा एक भी सीट जीतने में नाकाम रहे। दूसरी ओर पहली बार राजद ने 24 में 05 उम्मीदवार अपनी धुर विरोधी जाति भूमिहारों को दिया। इन पांचों में से 03 जीतने में कामयाब रहे और एक उम्मीदवार अपनी की चालबाजी के कारण मामूली अंतर से हार गया। मतलब साफ है। अब अगर राजद भूमिहार (सवणों) को आगे कर चुनावी मैदान में उतरती है तो इसके लिए जीत का स्ट्राइक रेट औसत से अधिक रहेगा और विधानसभा में 20 वर्षों का वनवास समाप्त होगा।

दरअसल, बिहार में भाजपा सहित पूरे एनडीए को खड़ा करने में सबसे मुखर भूमिका भूमिहारों की रही है, मगर छद्म सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर भाजपा सहित सभी एनडीए के घटक दलों ने इस जाति की उपेक्षा की। 20 साल बीतते बीतते सब्र का बांध टूटने लगा। अपने नेताओं की उपेक्षा ने इसे एनडीए से बागी होने पर मजबूर कर दिया। लिहाजा अगर राजद के टिकट पर 05 में तीन भूमिहार उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे तो इसे नये सामाजिक राजनीतिक समीकरण का सूत्रपात मानिए। हालांकि 24 विधानपरिषद की सीटों पर भाजपा 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जद (यू) 11 पर और लोजपा का पारस खेमा 01 सीट पर। 13 सीटों के साथ तीनों ने बहुमत तो पाया है, लेकिन इस जीत में भी इनकी हार है।

24 सीटों में से इनके पास 18 सीटें थी। लिहाजा 06 सीटों का सीधा नुकसान है। दूसरी ओर इस बार भाजपा 12 में से 07 सीट जीत पाई तो जद (यू) के पास 11 में से मात्र 05 सीटें ही रही। लोजपा का पारस खेमा 01 सीट पर लड़ी और जीतने में कामयाब रही। भाजपा वैश्य समुदाय के साथ तालमेल करते हुए अपनी सीट जीतती हुई दिख रही है। हालांकि वैश्य वर्ग के साथ के समीकरण में भाजपा के लिए नया कुछ नहीं है। वहीं वोटिंग पैटर्न बताता है कि अगर राजद का पलड़ा भारी हुआ तो महंगाई और अफसरशाही ये दो ऐसे शब्द हैं, जिनको आधार बनाकर ना सिर्फ वैश्य बल्कि रोजी रोटी की लड़ाई में पिछड़ा हर व्यक्ति राजद के साथ होगा। साथ ही राजनीति के शिकार चिराग पासवान और मुकेश सहनी भी एनडीए के खिलाफ ही मोर्चा खोलेंगे। लिहाजा गैर एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है।

दरअसल, 24 विधानपरिषद की सीटों पर हुए इस चुनाव ने हर दल को मौका दिया है। राजद के लिए नया समीकरण गढ़ने का अवसर है। एनडीए के लिए संभलने की चुनौती। एनडीए लगातार अपने कोर वोटर को किनारे कर कुछ प्रयोग कर रही है। ऐसा ना हो कि प्रयोगशाला की भट्टी में अपना ही चेहरा झुलस जाए। राजनीति सिर्फ विज्ञान नहीं सामाजिक विज्ञान है। आने वाले वक्त में हो सकता है ऐसा नारा सुनाई दे कि मोदी तुझसे बैर नहीं बिहार में एनडीए की खैर नहीं।

हालात इतनी तेजी से बिगड़े, दक्षिण कोरिया और चीन उसकी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पिछले साल अगस्त में श्रीलंका ने अचानक फूड इमर्जेंसी की घोषणा कर दी। यह एक तरह से आर्थिक आपातकाल का एलान ही था।

खाने-पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगे थे और पेट्रोल-डीजल के लिए लंबी लाइनें लग चुकी थीं। विदेशी निवेशकों ने बाजार से पैसे निकाले, तो हालात और गंभीर होते गए। श्रीलंका अपनी जरूरत की करीब-करीब सभी चीजें आयात करता है, यह उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। इस बीच बांग्लादेश, भारत,

हाथ खड़े करने को मजबूर श्रीलंका

आलोक जोशी
नए साल पर बुरी खबर! श्रीलंका के लोग बुधवार और गुरुवार को नया साल मना रहे हैं। आज सिंहली और गुरुवार को तमिल नववर्ष मनाया जाएगा, लेकिन कल ही यह बुरी खबर आई कि देश की आर्थिक स्थिति कंगाली के कगार पर पहुंच चुकी है। बाकायदा सरकारी एलान हुआ है। कई हफ्ते से चल रही कशमकश के बाद आखिरकार श्रीलंका सरकार ने एलान कर दिया है कि वह लगभग 51 अरब डॉलर के अपने विदेशी कर्ज का भुगतान करने या उसका ब्याज चुकाने की स्थिति में नहीं है। मतलब उसने लेनदारों को बता दिया है कि फिलहाल श्रीलंका ब्याज की किस्तों का भुगतान नहीं करेगा। श्रीलंकाई वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि उनके पास आयात के लिए विदेशी मुद्रा नहीं बची है, इसलिए यह आखिरी कदम उठाना पड़ा है। सवाल है कि श्रीलंका के कर्ज न लौटाने का मतलब क्या है और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? बात थोड़ी विकट है, इसलिए अपने आसपास से शुरू करना बेहतर होगा।

सात दिन में लौटाने का वादा करके किसी से उधार लिया हो और सातवें दिन खाते में आने

वाली वह रकम ही न आए, तो क्या हाल होता है? खुद नहीं, तो आसपास के लोगों के साथ ऐसा होते हुए हम सभी ने कभी न कभी देखा होगा। खुद न देखा हो, तो फिल्मों या टीवी धारावाहिकों के ऐसे नजरों याद करें। कभी लेनदार भला इंसान होता है, तो कभी कपड़े उतारने या सामान फेंकने तक की नौबत आ जाती है। पुरानी फिल्मों में वसूली करने वाले पठान और आजकल रिकवरी एजेंट यही काम करते हैं। कोई आम ग्राहक हो या बड़ी कंपनियां, कर्ज देते समय यह जरूर देखा जाता है कि वे इसे चुकाने की हैसियत रखती हैं या नहीं? और यह कर्ज वापस न आने का खतरा कितना बड़ा है? इससे तय होता है कि उस पर कितना ब्याज वसूला जा सकता है। ज्यादा जोखिम यानी ज्यादा ब्याज। यह गणित पूरी दुनिया में इसी तरह चलता है।

लेकिन दुनिया भर में एक बिरादरी ऐसी है, जिसे कर्ज देना बेहद सुरक्षित माना जाता है। यह बिरादरी है, अलग-अलग देशों की सरकारों की। इनसे कर्ज वापस मिलने की गारंटी मानी जाती है। इनकी संप्रभुता का ही असर है कि इन्हें दिए जाने वाले कर्ज साँवरेन लोन या इनकी गारंटी को साँवरेन गारंटी कहा जाता है। सरकारों के पास यह ताकत भी होती है कि वे

नोट छापकर भुगतान कर दें। मगर अंतरराष्ट्रीय लेन-देन में एक उम्सूल यह भी है कि जिस मुद्रा में कर्ज लिया जाए, उसी में लौटाना भी जाए, यानी श्रीलंका को अपना कर्ज डॉलर में चुकाना है, जिसके लिए उसके पास कोई इंतजाम बचा नहीं है। यही वजह है कि श्रीलंका सरकार ने कहा है कि लेनदार चाहें, तो श्रीलंकाई रुपये में भुगतान ले सकते हैं या फिर वे ब्याज की रकम को मूलधन में जोड़कर कर्ज की रकम बढ़ा सकते हैं।

जब किसी देश के डिफॉल्ट की खबर आती है, तो यूँ लगता है, मानो देश बैट गया। अब वहां ताला लग जाएगा। हालात होते तो गंभीर ही हैं। लेकिन आमकी मालूम होना चाहिए कि 1960 से अब तक 147 सरकारें अलग-अलग वक्त पर अपने कर्ज या उनके ब्याज की किस्त भरने में नाकाम रही हैं। आम तौर पर दुनिया में जब कोई बड़ा आर्थिक संकट आता है, तब ऐसे मामले बढ़ते हैं। साल 2008 के आर्थिक संकट के दौरान निकारागुआ और इक्वाडोर जैसे देशों के डिफॉल्ट की नौबत आई, बल्कि उसी संकट का असर था कि 2015 में ग्रीस के सामने भी ऐसी ही नौबत आ खड़ी हुई। इसे बड़ा संकट माना गया, क्योंकि यह किसी विकसित देश का डिफॉल्ट था और इसका दबाव पूरे यूरोपीय

संघ पर पड़ता देखा गया।

आज भी श्रीलंका अकेला नहीं है। हालांकि, दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं, लेकिन इस वक्त रूस भी इसी चुनौती से जूझ रहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय कर्ज के बाजार में डिफॉल्ट होने से कैसे बचे? रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने तो कह दिया है कि रूस डिफॉल्ट हो चुका है, क्योंकि उसने 4 अप्रैल को जो ब्याज की किस्तें भरी हैं, वे डॉलर के बजाय रूबल में भरी गई हैं।

रूस का संकट यह है कि यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका और पश्चिमी देशों ने उसे अंतरराष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क से काट दिया है। उसके सामने भी यह खतरा खड़ा हो गया है कि वह अपने लेनदारों की किस्त चुकाने की हालत में नहीं है। कह सकते हैं कि रूस ने यह मुसीबत खुद मोल ली है। मगर श्रीलंका की परिस्थिति अलग है। कुछ ही साल पहले भारत में उदाहरण दिए जाते थे कि श्रीलंका व बांग्लादेश किस तेजी से तरकी कर रहे हैं।

खासकर वस्त्र निर्यात के मामले में। श्रीलंका का पर्यटन कारोबार भी खूब फल-फूल रहा था, लेकिन कोरोना ने इस सब पर पानी फेर दिया और उसके बाद सरकार व कारोबार की बाकी कमजोरियां भी सामने आने लगीं।

मदद की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन अब जहां वह पहुंच गया है, वहां हल्की-फुल्की मदद से काम चलने वाला नहीं है। जानकारों का कहना है, सबसे जरूरी है कि श्रीलंका का राजनीतिक नेतृत्व बदले और ऐसे लोग सत्ता में आएँ, जिन पर वहां की जनता को भी भरोसा हो और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को भी। तब शायद वे कुछ कड़े कदम उठाने का फैसला कर सकें, और उस बिना पर दूसरे देशों से मदद भी जुटा पाएँ। श्रीलंका के ही नहीं, पूरे इलाके के बेहतर भविष्य के लिए ऐसा होना जरूरी है।



बढ़ रही है इमेज कंसल्टेंट सेवाओं की मांग

भारत में लगातार बढ़ती जा रही प्रतिस्पर्धा की वजह से अपनी इमेज मैनेज करना भी एक अहम जरूरत बन चुकी है। अधिक से अधिक लोग अब इस जरूरत को महसूस कर रहे हैं जिस वजह से देश में इमेज कंसल्टेंट की सेवाओं की मांग में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है।

इमेज कंसल्टिंग के तहत लोगों को अपने भीतर छुपी क्षमताओं को निखारने और साथ ही साथ उन क्षमताओं को सभी के समक्ष प्रदर्शित करने के लिए अपनी अपीयरेंस (दिखावट) के प्रबंधन हेतु मार्गदर्शन किया जाता है। इमेज कंसल्टिंग के तहत लोगों को परिधान पहनने व तैयार होने के टंग, बॉडी लैंग्वेज, शिष्टाचार एवं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में शिक्षित किया जाता है। इमेज कंसल्टेंट व्यक्तिगत रूप से तथा समूह में कोचिंग प्रदान करते हैं। वे किसी एक व्यक्ति अथवा कम्पनियों को अपनी सेवाएं देते हैं। वे लोगों के लिए मुक्त कार्यशाला भी आयोजित करते हैं। इस क्षेत्र से जुड़े कार्यों में पर्सनल शॉपिंग, यूनिफॉर्म डिजाइन, इमेज मैनेजमेंट, पॉलिशी डिजाइन, स्टाइलिंग आदि भी शामिल हैं। भारत में लगातार बढ़ती जा रही प्रतिस्पर्धा की वजह से अपनी इमेज मैनेज करना भी एक अहम जरूरत बन चुकी है। अधिक से अधिक लोग अब इस जरूरत को महसूस कर रहे हैं जिस वजह से देश में इमेज कंसल्टेंट की सेवाओं की मांग में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। यह ऐसा करियर है, जिसमें व्यक्ति अन्य लोगों के विकास का मुख्य सहयोगी बनता है तथा अन्य लोगों को और अधिक सफल बनाने से उसे सफलता मिलती है। यह क्षेत्र उन महिलाओं को करियर बनाने का दूसरा मौका देता है जिन्होंने कुछ समय के लिए अपने पहले करियर को छोड़ रखा हो। इमेज कंसल्टिंग बिजनेस इंस्टीट्यूट भारत में इमेज कंसल्टेंसी की शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने वाला अग्रणी संस्थान होने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भी एक

प्रतिष्ठित संस्थान है। यह संस्थान इमेज कंसल्टिंग एवं बिजनेस प्रोग्राम संबंधी अनेक पेशेवर कोर्स कराता है। इस संस्थान की डायरेक्टर सुमन अग्रवाल भारतीय उपमहाद्वीप की वरिष्ठतम इमेज कंसल्टेंट मानी जाती हैं। उनकी कहानी भी एक उत्तम प्रेरणा स्रोत है। उन्हें कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी थी परंतु आज वह एक सफल उद्यमी तथा इस संस्थान के प्रमुख हैं। यूनाइटेड किंगडम स्थित फैडरेशन ऑफ इमेज प्रोफेशनल इंटरनेशनल द्वारा उन्हें इमेज मास्टर अवार्ड से नवाजा गया जिससे वह भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वाधिक वरिष्ठ इमेज कंसल्टेंट बन गईं। इमेज कंसल्टिंग में पहनावे के महत्व पर वह कहती हैं, "80 प्रतिशत से अधिक संवाद दृश्य होता है और पहनावा इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो व्यक्ति का सबसे अधिक ध्यान सामने वाले के पहनावे पर ही जाता है। हालांकि यह बातना जरूरी है कि पहनावे के संबंध में कोशल एक इमेज कंसल्टेंट के पास होता है, वह सर्वश्रेष्ठ फेशन डिजाइनर समेत किसी अन्य पेशेवर के पास नहीं हो सकता है। महत्व बढ़िया परिधानों का नहीं होता, बल्कि उस संदेश का होता है जो आप अपने पहनावे से सामने वाले को देना चाहते हैं। सही पहनावे को सुनिश्चित बनाने के लिए व्यक्ति को अपने काम, लक्ष्यों एवं मौके का ध्यान रखने के अलावा आकर्षक दिखने के लिए अपने शारीरिक ढांचे, रंग-रूप, चेहरे के आकार आदि पर भी गौर करना पड़ता है।" उनके अनुसार इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए यह एक उत्तम एवं बेहद लाभदायक करियर साबित हो सकता है।

करियर उन्मुखी होते हैं पत्राचार पाठ्यक्रम

आज सभी विषयों में वैज्ञानिक तथा मास्टर डिग्री कोर्स के अलावा अनेक सर्टिफिकेट कोर्स एवं डिप्लोमा भी पत्राचार माध्यम से दूरस्थ शिक्षा के रूप में उपलब्ध हैं। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को सभी संबंधित विषयों का बुनियादी ज्ञान प्रदान करना होता है।

कुछ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश एक चयन परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है। पत्राचार शिक्षा ने हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया है। पत्राचार माध्यम से अध्ययन करने वाले छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न आधुनिक तकनीकों का सहारा भी दिया जा रहा है। देश में अनेक मुक्त विश्वविद्यालय तथा उससे भी अधिक नियमित विश्वविद्यालय तथा कई अन्य संस्थाएं दूरस्थ अध्ययन कार्यक्रम चलाते हैं। दूरस्थ शिक्षा पद्धति कई श्रेणियों के शिक्षार्थियों, विशेष रूप से देरी से पढ़ाई शुरू करने वालों, जिन व्यक्तियों के घर के पास उच्चतम शिक्षा साधन नहीं है, संचालित व्यक्तियों और अपनी शैक्षिक योग्यताएं बढ़ाने के इच्छुक व्यक्तियों को लाभ प्रदान कर रही है। मुक्त विश्वविद्यालय ऐसे लचीले पाठ्यक्रम विकल्प देते हैं जिन्हें वे छात्र ले सकते हैं जिनके पास कोई औपचारिक योग्यता नहीं है किन्तु अपेक्षित आयु (प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 18 वर्ष) के हो चुके हैं और लिखित प्रवेश परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। ये पाठ्यक्रम छात्र अपनी सुविधानुसार भी ले सकते हैं। विश्वविद्यालयों के दूरस्थ शिक्षा केंद्र न्यूनतम पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश देते हैं। यह पात्रता नियमित पाठ्यक्रमों के समान ही होती है। पत्राचार शैक्षिक संस्थाएं छात्रों को पाठ्यक्रम सामग्री के साथ-साथ संपर्क कक्षाएं भी उपलब्ध कराती हैं और परीक्षाएं संचालित करती हैं। अधिकांश विश्वविद्यालय मुदित अध्ययन सामग्री के अलावा अपने स्थानीय केंद्रों पर मल्टीमीडिया साधनों से भी छात्रों को शिक्षित करते हैं। ये विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम, मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम, एम.फिल पीएच.डी. तथा डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम भी चलाते हैं जिनमें से अधिकांश पाठ्यक्रम करियर उन्मुखी होते हैं।



कॉस्मेटिक समस्याओं का निदान करते हैं डर्मटोलॉजिस्ट

डिसिन में स्पेशलाइजेशन के लिए उपलब्ध विकल्पों में 'डर्मटोलॉजी' काफी लोकप्रिय हो गया है। मौजूदा वक्त में 'फर्सट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन' कहावत को इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है कि व्यक्ति के रूप को व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण अंग माना जाने लगा है। इस कारण लोगों में अपने रूप और व्यक्तित्व को लेकर चिंता का स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। यहां तक कि कॉलेज जाने वाले छात्र भी खुद को आकर्षक दिखाने की गरज से काफी रूपरेखा खर्च कर रहे हैं। अपने रूप को लेकर लोगों में गंभीरता का स्तर इस कदर बढ़ गया है कि वह चेहरे पर छोटा-सा मुहासा हो जाने भर से परेशान हो उठते हैं। कई बार वह ऐसी परेशानियों को इस कदर अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि घर से बाहर निकलना भी छोड़ देते हैं। ऐसे माहौल में रूप निखारने का दावा करने वाली फेयरनेस क्रीमों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। खुजली और घर्षणियों (रैशज) जैसे त्वचा संबंधी रोग आम हो चुके हैं। गर्मी और बरसात के मौसम में इनकी अधिकता काफी बढ़ जाती है। इनके सही उपचार के लिए डॉक्टर का परामर्श जरूरी होता है। कई बार उपचार के लिए डॉक्टर के पास कुछ दिनों या हफ्तों के अंतराल पर बार-बार जाने की जरूरत होती है। ऐसे में लोग अपनी त्वचा के लिए ज्यादा खर्च करने में जरा भी नहीं हिचकते। त्वचा और रूप के प्रति लोगों के बढ़ती सजगता के कारण डर्मटोलॉजिस्ट की मांग में इजाफा हो रहा है। डर्मटोलॉजी मेडिसिन की एक शाखा है, जिसमें त्वचा और

उससे संबंधित रोगों के निदान का अध्ययन किया जाता है। यह एक स्पेशलाइज्ड विषय है, जिसकी पढ़ाई एमबीबीएस के बाद होती है। डर्मटोलॉजिस्ट रोगों के उपचार के अलावा त्वचा, बाल और नाखूनों से संबंधित कॉस्मेटिक समस्याओं का भी निदान करते हैं।

डर्मटोलॉजिस्ट का काम
इनका मुख्य कार्य लोगों की उन बीमारियों का उपचार करना होता है, जो त्वचा, बाल, नाखूनों और मुंह पर दुष्प्रभाव डालती हैं। एलर्जी से प्रभावित त्वचा, त्वचा संबंधी दागों, सूर्य की रोशनी में झुलसे या अन्य तरह के विकारों से ग्रसित त्वचा को पूर्व अवस्था में लाने में ये रोगियों की मदद करते हैं। इसके लिए वह ऐसी परेशानियों को इस कदर अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि घर से बाहर निकलना भी छोड़ देते हैं। ऐसे माहौल में रूप निखारने का दावा करने वाली फेयरनेस क्रीमों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। खुजली और घर्षणियों (रैशज) जैसे त्वचा संबंधी रोग आम हो चुके हैं। गर्मी और बरसात के मौसम में इनकी अधिकता काफी बढ़ जाती है। इनके सही उपचार के लिए डॉक्टर का परामर्श जरूरी होता है। कई बार उपचार के लिए डॉक्टर के पास कुछ दिनों या हफ्तों के अंतराल पर बार-बार जाने की जरूरत होती है। ऐसे में लोग अपनी त्वचा के लिए ज्यादा खर्च करने में जरा भी नहीं हिचकते। त्वचा और रूप के प्रति लोगों के बढ़ती सजगता के कारण डर्मटोलॉजिस्ट की मांग में इजाफा हो रहा है। डर्मटोलॉजी मेडिसिन की एक शाखा है, जिसमें त्वचा और

पता लगाते हैं कि रोग की वजह क्या है। रोग का पता लगने के बाद उपचार शुरू कर देते हैं। इस कार्य में वह दवाओं, सर्जरी, सुपरफिशियल रेडियोथेरेपी या अन्य उपलब्ध उपचार विधियों का उपयोग करते हैं।

करते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी
चेहरे और अन्य अंगों को आकर्षक बनाने के लिए डर्मटोलॉजिस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी भी करते हैं। त्वचा की झुर्रियों और दाग-धब्बों को खत्म करने के लिए वह इन्फ्रेशन जैसी तकनीक और बोटोक्स इन्जेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इन तकनीकों के अलावा वह लेजर थेरेपी का भी उपचार में उपयोग करते हैं। इस तकनीक की मदद से वह झुर्रियों और त्वचा पर होने वाले स्फेद दाग का इलाज करते हैं।

योग्यता - फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ बराबरी पास करके एमबीबीएस डिग्री प्राप्त करना डर्मटोलॉजिस्ट बनने की पहली शर्त है। इसके बाद डर्मटोलॉजी, वेनेरियोलॉजी और लेप्रोलॉजी में तीन वर्षीय एमडी या दो वर्षीय डिप्लोमा की पढ़ाई की जा सकती है।



लोगों में प्रतिमा तो होती है परंतु उसे समझने और निखारने की आवश्यकता होती है, उन्हें प्रशिक्षण मुहैया कराने के लिए कई संस्थानों में संबंधित कोर्स संचालित किए जा रहे हैं।

करियर को दिशा देती है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग

सॉफ्ट स्किल की क्षमता आपके करियर को नई दिशा देती है, अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग तकनीकी रूप से बड़े प्रतिभावान होते हैं, साथ ही, वे अपने क्षेत्र में निपुण भी होते हैं किंतु एक निश्चित बिंदु पर उनके करियर में ठहराव-सा आ जाता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें नेतृत्व क्षमता, समूह में काम करना, सामाजिक सम्बंध और संबंध निर्माण आदि कौशल का अभाव होता है। सॉफ्ट स्किल व्यापक क्षेत्र है, जिसमें सम्बंध कौशल, श्रवण कौशल, टीम कौशल, नेतृत्व कौशल, सृजनात्मकता और तर्कसंगत, समस्या निवारण, कोशल और परिवर्तनशीलता आदि सम्मिलित हैं। सॉफ्ट स्किल के गुण किताबों से नहीं सीखे जाते, बल्कि इसके लिए प्रशिक्षण कारगर होते हैं। यदि आप सही अर्थों में अपने व्यक्तित्व में सॉफ्ट स्किल्स जोड़ना चाहते हैं तो आपको एक अच्छे, मेहनती और सीखने वाला बनकर उन सब बातों को, जो कुछ भी आपने व्यावहारिक रूप से ग्रहण किया है, व्यवहार में लाना होगा, कुछ ऐसे सॉफ्ट स्किल्स भी हैं जो आपकी रोजगार की संभावनाओं और व्यक्तित्व में सुधार कर स्यायी और अच्छी सैलरी पर नौकरी प्राप्त करने में सहयोग करती है।

संगठन में कार्य करते हैं, ऐसी दवावर्णन स्थितियों का मुकाबला करने के लिए आपको कुछ ऐसे कौशल विकसित करने की आवश्यकता है जो आपको निर्णय लेने, सृजनात्मक एवं अन्वेषणात्मक समाधान विकसित करने, व्यावहारिक हल ढूँढने, समस्याओं का स्वतंत्र रूप से पता लगाने, उनको हल करने और विभिन्न क्षेत्रों में समस्याओं के निदान में कार्य नीतियां लागू करने में मददगार हो सकते हैं।

नौकरियां
आजकल ज्यादातर संगठन अपने कर्मचारियों में उनके सकारात्मक, सम्बंध, अंतर्व्यक्तिक और टीम कौशल, समस्या निदान, अनुकूलनशीलता और कार्य पद्धति में सुधार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, इससे एक तरफ जहां उनके व्यवसाय और व्यक्तित्व जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ स गठन की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है, अतः सॉफ्ट स्किल में पाठ्यक्रम पूरा करने के उपरांत कोई व्यक्ति किसी निजी या सार्वजनिक संगठन में सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षक के रूप में रोजगार प्राप्त कर सकता है, इसके अलावा, आप अपना स्वयं का ट्रेनिंग सेंटर भी खोल सकते हैं।

सामूहिक कार्य
कोशल अंतर्व्यक्तिक और सामूहिक कार्य कौशल उच्चतर उत्पादकता तथा बेहतर वातावरण के लिए योगदान करते हैं क्योंकि इनसे व्यक्ति संयुक्त लक्ष्य हासिल करने हेतु मिलकर कार्य करते हैं, यह सम्बंध टीम सदस्यों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया की स्थापना, फीडबैक का आमंत्रण, उसे प्रदान करना तथा संघर्ष की स्थिति को हल करना अपेक्षित होता है।

ज्ञानात्मक कौशल
आपने रोजमर्रा के जीवन में अक्सर आपको ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जब आप सही फैसले करने में असमर्थ होते हैं, आपके सामने ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने की ज्यादा संभावनाएं उस वक्त होती हैं जब आप किसी



व्यक्तित्व संबंधी गुण

समय के साथ-साथ अब फोकस एक सामान्य व्यक्ति से सुशिक्षित और परिष्कृत व्यक्तित्व की ओर हो गया है, विभिन्न संगठनों, खासकर कंपनियों को ऐसे व्यक्तियों की तलाश रहती है जो कुशाग्र और सुशिक्षित होते हैं, उनमें ऐसे सम्बंध कौशल होने चाहिए कि वे सबसे आगे रहें, इसके लिए वे अपने कर्मचारियों को भर्ती के उपरांत प्रशिक्षण प्रदान करते हैं लेकिन वे उन व्यक्तियों को वरीयता देते हैं जो पहले से अपने क्षेत्र में बेहतर होते हैं, चूंकि ज्यादातर लोग प्रतिभाओं के साथ जन्म लेते हैं, परंतु उन्हें परिष्कृत और शिक्षित करने की आवश्यकता होती है, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बाजार में बहुत से संस्थान संचालित किए जा रहे हैं, ये संस्थान काफी धन अर्जन कर रहे हैं और इस तरह सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षकों को आकर्षक रोजगार का विकल्प प्रदान कर रहे हैं।

वेतन

इस सेक्टर में काफी अच्छे वेतन है, चूंकि यह कल्चर प्राइवेट कंपनियों और वैश्वीकरण के कारण तेजी फला-फूला है, इसलिए इसकी प्रोथ भी ज्यादा है।

योग्यताएं

पहले इस फील्ड में पाठ्यक्रम नहीं चलाए जाते थे लेकिन अब सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षकों के लिए शिक्षण कार्य भी एक अच्छे विकल्प के रूप में उभरकर सामने आया है क्योंकि सभी इंजीनियरिंग और प्रबंध संस्थानों में तकनीकी कौशल एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल होता है, वहां पर छात्रों को साक्षात्कार और समूह चर्चा में बेहतर प्रदर्शन के लिए अपेक्षित अन्य वैयक्तिक कौशलों के साथ-साथ प्लेसमेंट और सम्बंध कौशलों के लिए प्रशिक्षित और तैयार किया जाता है।



पहली बार में क्रेक करना है आईआईटी जेईई तो अपनाएं ये आसान टिप्स

जेईई मेन्स जेईई मेन्स की परीक्षा में अच्छे पर्सेंटाइज लाने वाले कैंडिडेट्स जेईई एडवांस्ड की तैयारी में जुट चुके हैं। साल भर की मेहनत तो बेहतर रिजल्ट का कारण है ही साथ ही परीक्षा से पहले अंतिम दिनों की मेहनत भी अत्यधिक मायने रखती है। आज हम आपको यहां बता रहे हैं जेईई मेन्स परीक्षा को क्रेक करने और एडमिशन पाने की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए जरूरी टिप्स।

अगर आप आईआईटी एगजाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ जरूरी टिप्स को अपनाना बिल्कुल न मूलें। इनकी मदद से आप पहली बार में एगजाम विलयर कर पाएंगे

ऐसे करें एगजाम की तैयारी

- अपनी सिली मिस्टेक्स पर काम करने का प्रयास करें क्योंकि इससे आपके ओवरऑल स्कोर में सुधार होगा।
- मॉक टेस्ट लेने और पिछले वर्ष के प्रश्नों को ऑनलाइन हल करने से आपको विभिन्न प्लाटफॉर्म को एनालाइज करने में मदद मिलेगी।
- सबकोट वाइज फॉर्मूला शीट तैयार करें, ऐसा करके आप फॉर्मूले को रिवाइज करने करने के लिए हर समय अपने साथ रख सकते हैं।
- एक डेली टाइम टेबल तैयार करें और मुख्य रूप से रिवीजन और ऑनलाइन टेस्ट पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि ये टेस्ट आपके स्कोर को 40-50% तक सुधारने में मदद करते हैं।
- स्टडी के दौरान छोटे ब्रेक लें या संगीत सुनें क्योंकि यह कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है।
- सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा नजदीक आने पर खुद को स्वस्थ और फिट रखें।

जेईई एडवांस्ड फिजिक्स को क्रेक करने के टिप्स

- फॉर्मूले अच्छी तरह से सीखें : जैसे ही आप फिजिक्स का रिवीजन करते हैं, सभी फॉर्मूले को नोट कर लें और उन्हें अच्छी तरह से याद रखें।
- स्कोरिंग टॉपिक पर कंसंटेंट करें : एक बार आपके बेसिक चैप्टर को रिविजन करने के बाद, मॉडर्न फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स, अल्ट्रासेटिंग कंटेंट, साउंड वेव्स जैसे क्वॉरिग टॉपिक्स पर ध्यान केंद्रित करें।
- थर्मोडायनामिक्स पर अतिरिक्त ध्यान दें क्योंकि यह फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सामान्य है।
- डेलिगेट प्रैक्टिस : जेईई एडवांस्ड पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना आवश्यक है। इन्हें सॉल्व समय फोकस और कॉन्फिडेंट रहें।

जेईई एडवांस्ड केमिस्ट्री क्रेक करने के टिप्स

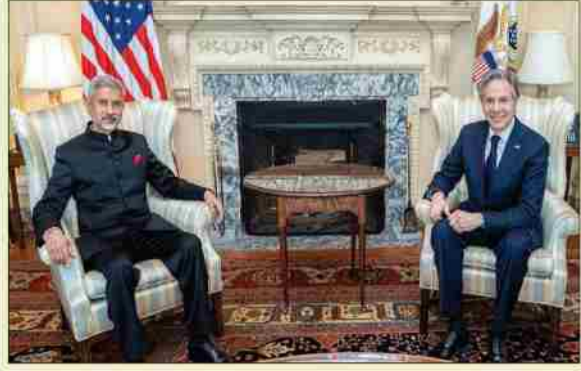
- अपनी प्रिपरेशन को सिस्टमेटिक रूप से तैयार करें : फिजिक्स और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना शुरू करें। अपने समय का एक बड़ा हिस्सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी में दें।
- लास्ट 5 दिनों के लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस छोड़ दें क्योंकि इसमें मुख्य रूप से याद रखने की आवश्यकता होती है।
- ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल मैकनिज्म पहली बार में जटिल लग सकता है। कठिन टॉपिक के लिए ज्यादा गहराई में न जाएं क्योंकि अंतिम दिनों में समय की कमी होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए छोटे नोट्स बनाने की जरूरत होती है।
- रिएक्शन की प्रैक्टिस करें : सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स, इन्वेंशन, मैकनिज्म और रिसेटेट प्रॉब्लमस का रेगुलर प्रैक्टिस करें।
- रेगुलर रिवीजन : केमिस्ट्री कई छात्रों को कंप्यूज कर देने की जरूरत होती है। बेहतर रिटेंशन के लिए केमिस्ट्री का रेगुलर रिवीजन जरूरी है।

जेईई एडवांस्ड मैथ्स को क्रेक करने के टिप्स

- कॉन्सेप्टुअल विलियरिटी : पहले सभी चैप्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। मैथ्स फॉर्मूला से भरा है। उन्हें अच्छी तरह से करने के लिए, फॉर्मूला के विभिन्न एप्लीकेशन की प्रैक्टिस करें।
- मॉक टेस्ट दें : फुल लेंथ वाले जेईई एडवांस्ड मॉक टेस्ट देने से आपकी स्पीड और एक्ज्यूटिविटी में सुधार करने में मदद मिलती है।
- प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करें : प्रत्येक चैप्टर को रिवाइज करने के बाद जेईई एडवांस्ड लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करना आवश्यक है।
- पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करें : जब आप जेईई एडवांस्ड मैथ्स की तैयारी कर रहे हों तो जेईई एडवांस्ड पिछले साल के टेस्ट से प्रैक्टिस करना जरूरी है।

सार समाचार

जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से मुलाकात की



वाशिंगटन। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को अपने अमेरिकी समकक्ष एंटी ब्लिंकन से मुलाकात कर वैश्विक स्थिति, क्षेत्रीय मुद्दों व द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। जयशंकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सोमवार को भारत-अमेरिका के बीच टू प्लस टू मंत्रिस्तरीय वार्ता में भाग लेने के लिए वाशिंगटन में हैं। बाइडेन प्रशासन के तहत दोनों देशों के बीच यह पहली टू प्लस टू मंत्रिस्तरीय वार्ता है। वार्ता की मेजबानी विदेश मंत्री ब्लिंकन और रक्षा मंत्री ऑस्टिन लॉयड कर रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दिन की शुरुआत अपने अमेरिकी समकक्ष ब्लिंकन के साथ नाश्ते पर हुई बैठक से की। विदेश मंत्री ने टवीट किया, 'हमने दिन की शुरुआत विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन के साथ नाश्ते पर हुई बैठक के साथ की। वैश्विक स्थिति, क्षेत्रीय मुद्दों और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। बैठक सफल और खुले वातावरण में हुई। भारत-अमेरिका टू प्लस टू मंत्रिस्तरीय वार्ता से पहले, जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुए डिजिटल शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने टू प्लस टू बैठक के मार्गदर्शन के लिए दोनों नेताओं को धन्यवाद दिया।

नए साल के जश्न से पहले भारत से 11,000 टन चावल श्रीलंका पहुंचा

कोलंबो। श्रीलंका के पारंपरिक नए साल से पहले भारत से 11,000 टन चावल की खेप मंगलवार को यहां पहुंची। आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका के लिए नए साल के जश्न से पहले यह बड़ी राहत है। श्रीलंका के लोग 13 और 14 अप्रैल को सिंहल और तमिल नव वर्ष मनाएंगे। यह श्रीलंका के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। भारतीय उच्चयोग ने कहा कि श्रीलंका के लोगों द्वारा नए साल के जश्न से पहले भारत से चावल की खेप कोलंबो पहुंच गई। बयान में कहा गया कि पिछले एक हफ्ते में श्रीलंका को भारत की मदद के तहत 16,000 टन चावल की आपूर्ति की गई है। भारतीय उच्चयोग ने कहा कि ये आपूर्ति आगे भी जारी रहेगी, जो भारत और श्रीलंका के बीच विशेष संबंधों को दर्शाती है। इस बीच श्रीलंका ने मंगलवार को घोषणा की कि वह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत पैकेज मिलने तक अपने विदेशी कर्ज में चूक करेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा, 'यह श्रीलंका सरकार की नीति होगी कि वह सामान्य ऋण सेवाओं को निलंबित कर दे... यह 12 अप्रैल 2022 को बकाया ऋणों पर लागू होगी।'

नेपाली वित्त मंत्री ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चल रही

काठमांडो। नेपाली वित्त मंत्री ने विपक्षी दलों के दावों को खारिज कर दिया कि आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था और खराब होगी। वहीं देश का आर्थिक प्रदर्शन सकारात्मक है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (सीपीएम-यूएमएल) से जुड़े नेपाल के तीन पूर्व वित्त मंत्रियों, विष्णु पौडेल, सुरेंद्र पांडेय और डॉक्टर राज खत्रीवाड़ा ने ताजा आर्थिक हालात के बारे में 12-बूटीय संयुक्त बयान जारी किया था। उन्होंने अर्थसूचना जताया कि देश की अर्थव्यवस्था संकट की ओर बढ़ रही है, इस सकारात्मक हस्तक्षेप के जरिए सही रास्ते पर लाना चाहिए। नेपाली वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा ने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में दावा किया कि रणनीतिक विचारों के आधार पर देश अब तक किसी बड़े आर्थिक संकट से नहीं गुजरा है। शर्मा ने तीन पूर्व वित्त मंत्रियों द्वारा जारी संयुक्त बयान को खारिज कर दिया। शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे पर गलत सूचना व्यापारियों को हतोत्साहित करने और लोगों को गुमराह करने के इरादे से फैलाई जा रही है, इस रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सतक और जागरूक है।

चीन से आयातित टायरों पर डंपिंग-रोधी शुल्क जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करेगा डीजीटीआर

नयी दिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने चीन से आयातित कुछ प्रकार के न्यूमैटिक रेडियल टायर पर डंपिंग-रोधी शुल्क को जारी रखने के लिए समीक्षा शुरू की है। घरेलू उद्योग से इस बारे में शिकायतें मिलने के बाद यह समीक्षा की जा रही है। वाहन टायर विनिर्माता संघ (एटीएमए) ने डीजीटीआर के समक्ष इस बारे में शिकायत दर्ज कराई है। एटीएमए ने चीन से आयातित नए/बिना इस्तेमाल वाले न्यूमैटिक रेडियल टायर, टयूर वाले और टयूरलेस टायरों पर लागू डंपिंग-रोधी शुल्क की समीक्षा की मांग की है। इन टायरों का इस्तेमाल बस और ट्रक/लॉरी में होता है। डीजीटीआर ने अधिसूचना में कहा कि प्राधिकरण डंपिंग-रोधी शुल्क को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा कर रहा है। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि क्या टायरों पर डंपिंग-रोधी शुल्क के समाप्त होने से घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचेगा। केंद्र सरकार ने न्यूमैटिक रेडियल टायर पर डंपिंग-रोधी शुल्क 18 सितंबर, 2017 को लगाया था। यह इस साल 17 सितंबर को समाप्त हो रहा है।

ब्रिटिश अध्ययन में वायु प्रदूषण से बड़े भारतीय शहरों में अधिक लोगों की मौत की बात सामने आई

लंदन। ब्रिटेन में हुए एक नये अध्ययन में सामने आया है कि भारत के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण के कारण कम उम्र में लोगों की मृत्यु के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले कुछ सालों में यह संख्या लगभग एक लाख तक रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (यूसीएल) में अनुसंधानकर्ताओं के नेतृत्व में हुए अध्ययन का प्रकाशन पिछले सप्ताह हासाइंस एडवांसमेंट में किया गया। इसमें निष्कर्ष निकला है कि तेजी से बढ़ते उपकटिबंधीय शहरों में 14 साल में करीब 1,80,000 लोगों की मौत वायु प्रदूषण बढ़ने की वजह से हुई, जिन्हें बताया जा सकता था। दक्षिण एशिया के शहरों में वायु प्रदूषण के प्रकोप से कम आयु में लोगों की मृत्यु के मामले बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गयी और बांग्लादेश के शहरों में ऐसे सर्वाधिक मामले आये जिनकी संख्या 24 हजार थी। इसके साथ ही भारत के मुंबई, बैंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, सूरत, पुणे और अहमदाबाद में ऐसे कुल एक लाख मामले आये। प्रमुख अनुसंधानकर्ता डॉ. कर्ण वोहरा ने कहा, 'जमीन साफ करने और कृषि की परंपरा के निराकरण के लिए जैव ईंधन को खुलेआम जलाना अतीत में उपकटिबंधीय प्रदेशों में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ने का बड़ा कारण रहा है।' उन्होंने कहा, हाइड्रोकार्बन विक्षेपण करता है कि हम इन शहरों में वायु प्रदूषण के नये युग में प्रवेश कर रहे हैं और कुछ शहरों में स्थिति एक साल में इतनी बिगड़ रही है जितनी दूसरे शहरों में एक दशक में बिगड़ती है।

भारी-भरकम कर्ज में डूबे श्रीलंका ने खुद को दिवालिया घोषित किया, चीन समेत सभी देशों के पैसों का क्या होगा?

कोलंबो। (एजेंसी)

श्रीलंका के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। देश में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, जनता राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से पूछ रही है कि आखिर हमारा देश कंगार क्यों हो गया है? देश का खजाना खाली हो गया है और खाने-पीने के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन अब आर्थिक संकट से जुड़ा रहे श्रीलंका ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने मंगलवार एलान किया है कि वो अपने 51

बिलियन डॉलर के विदेशी कर्ज को नहीं चुका पाएगा। हफ्तों की आर्थिक उथल-पुथल के बाद, श्रीलंका के द्वीप राष्ट्र ने मंगलवार को घोषणा की कि वह आयात के लिए विदेशी मुद्रा से बाहर निकलने के बाद अपने सभी विदेशी ऋण 51 बिलियन डॉलर का कर्ज नहीं चुका पाएगा।

वित्त मंत्रालय ने कही ये बात
द्वीप राष्ट्र नियमित रूप से ब्लैकआउट और भोजन और ईंधन की भारी कमी के साथ स्वतंत्रता के बाद से सबसे खराब आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। श्रीलंका के

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विदेशी सरकारों सहित लेनदार मंगलवार से अपने किसी भी ब्याज भुगतान के लिए या तो इंतजार करें या फिर श्रीलंकाई रुपये में भुगतान का विकल्प चुनें।

श्रीलंका पर कितना कर्ज

श्रीलंका पर चीन का 5 बिलियन डॉलर का कर्ज है। इसके अलावा चीन से श्रीलंका ने 1 बिलियन डॉलर का कर्ज, और लिया है, जिसको वो किरतों में चुकाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ 500 मिलियन डॉलर के सोवरेन बॉन्ड्स भी श्रीलंका पर बकाया

हैं। देश के कुल लोन में चीन का कर्ज 15 फीसदी के आसपास है। देश पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का 13 फीसदी, वर्ल्ड बैंक का 10 फीसदी, जापान का 10 फीसदी और भारत का 2 फीसदी कर्ज है।

कैसे तय होता है पैमाना

किसी देश को दिवालिया घोषित करने में एक साथ कई आर्थिक ताकतें काम करती हैं। किसी देश को दिवालिया घोषित करना किसी कंपनी को दिवालिया घोषित करने की तरह नहीं है। लेकिन एक देश के मौद्रिक नीति की स्थिति कई

कारकों के ऊपर होते हैं जो किसी देश की हैसियत को बताते हैं। इसके साथ ही निवेशकों का भरोसा भी किसी देश के दिवालियापन की हैसियत को बताता है। जिसमें मूडीज जैसी कंपनी की रेटिंग बड़ी भूमिका अदा करती है। रेटिंग एजेंसियां देश की वित्तीय जिम्मेदारी का इतिहास और पिछली देनदारियों में चूक और आईएमएफ के वर्तमान कर्ज अदायगी की योजनाओं को देखकर कर्ज देती हैं। जब कोई देनदार अपने कर्जदार को अदायगी समय पर नहीं कर पाता तो उसे दिवालिया कह दिया जाता है।



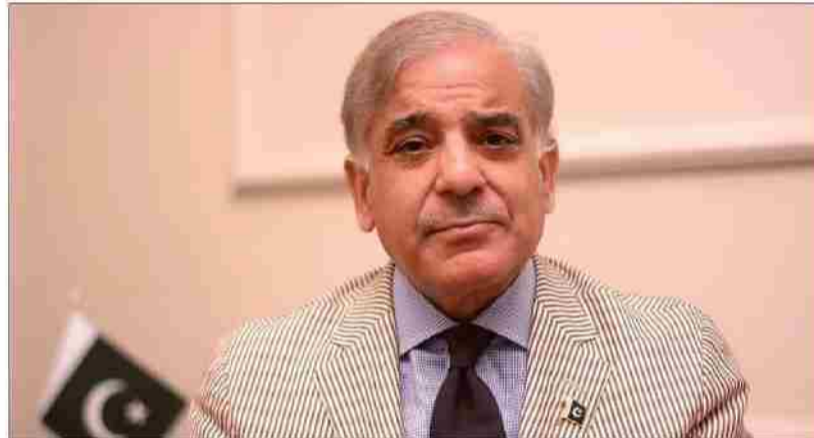
चीन में शंघाई के कुछ इलाकों में कोरोना संक्रमण के कारण लगी पाबंदियों में मिली राहत के बाद एक सड़क से गुजरते हुए रहवासी।

पीएम मोदी के बधाई संदेश पर आया शहबाज शरीफ का जवाब, फिर अलापा कश्मीर राग

इस्लामाबाद। (एजेंसी)

नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बन चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को ट्विटर के जरिए बधाई भी दी थी। अब शहबाज शरीफ ने मोदी के बधाई संदेश का जवाब दिया है। हालांकि अपने जवाब में शहबाज शरीफ ने कश्मीर का भी राग अलापा है। मोदी के संदेश के जवाब में शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर लिखा कि बधाई के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगी संबंध चाहता है। जम्मू-कश्मीर सहित बकाया विवादों का शांतिपूर्ण समाधान अपरिहार्य है। आतंकवाद से लड़ने में पाकिस्तान की कुबानी जगजाहिर है।

इसके साथ ही शहबाज शरीफ ने लिखा कि आइए शांति सुरक्षित करें और अपने लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान दें। आपको बता दें कि अपने बधाई संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया था कि भारत आतंकवाद मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है। मोदी ने लिखा कि मुहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के रूप में चुने जाने पर बधाई। भारत आतंक



मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है, ताकि हम अपनी विकास की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अपने लोगों की भलाई और समृद्धि सुनिश्चित कर सकें। वहीं, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहबाज शरीफ को बधाई दी थी। अपने बधाई संदेश में राजनाथ ने कहा था कि मैं उनको कहना चाहूंगा कि वह आतंकवाद पर नकेल कसें। उन्हें शुभकामनाएं। आपको बता दें कि दोनों ही देशों के बीच आतंकवाद के मुद्दे को लेकर बातचीत बंद है। भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब

तक पाकिस्तान अपने क्षेत्र में आतंकियों को पनाह देना बंद नहीं करता तब तक उससे बातचीत नहीं होगी। दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से लगातार कश्मीर राग अलापा जाता है। शहबाज शरीफ ने भी कश्मीर को लेकर अपनी बात रखी है। शहबाज शरीफ ने पहले ही भाषण में कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि घाटी में लोगों का 'खून बह' रहा है और पाकिस्तान उन्हें 'कूटनीतिक और अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा उठाएगा।

मारियोपोल में रूसी हमले में 10 हजार से अधिक नागरिकों की मौत, सड़कों पर बिछी लाशें

कीव। (एजेंसी)

रूसी सेना की ओर से यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह शहर मारियोपोल में पिछले छह सप्ताह से लगातार किए जा रहे हमलों में अब तक 10 हजार से अधिक नागरिकों की मौत हो चुकी है। मारियोपोल के मेयर वादिम बॉयचेंको ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि लोगों को लाशें सड़कों पर कालीन की तरह बिछी हैं।

इस बीच, पश्चिमी देशों का कहना है कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस रूसी सेना का एक काफिला यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में बढ़ रहा है और वहां एक बड़ा हमला होने की आशंका है। मारियोपोल में पिछले छह सप्ताह के दौरान सबसे भीषण हमले हुए हैं और यहां आम नागरिकों को बेहद मुश्किल हालात का सामना करना

रूस की फिनलैंड और स्वीडन को चुनौती, नाटो में शामिल हुए तब अंजाम सही नहीं होगा

मार्स्को (एजेंसी)

यूक्रेन और रूस के बीच नाटो को लेकर इतना बड़ा युद्ध छिड़ गया, उसी राह पर फिनलैंड और स्वीडन भी आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इस कारण मार्स्को ने इन दोनों ही देशों को खुली चेतावनी दे दी है, कि यदि ऐसा हुआ तब अंजाम सही नहीं होगा। क्रैमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्काव का कहना है, कि फिनलैंड और स्वीडन का ये फैसला यूरोप में अस्थिरता ला सकता है। रूस ने साफतौर पर कहा है कि इन दोनों का ये फैसला संघर्ष के रास्ते पर ला सकता है। रूस की तरफ से ये बयान उस समय में दिया गया है, जब अमेरिका ने यूक्रेन पर रूस के हमले को एक बड़ी रणनीतिक भूल करार दिया है। अमेरिका का कहना है कि रूस की भूल ने नाटो के विस्तार को मौका दे दिया है।

बता दें कि इसी वर्ष जून में नाटो का सम्मेलन मैड्रिड में होगा। सम्मेलन से पहले ही नाटो प्रमुख स्टोल्टेनबर्ग के बयान ने फिर से राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर पारा बढ़ाने का काम किया है। स्टोल्टेनबर्ग का कहना है, कि यदि ये दोनों देश नाटो में



शामिल होना चाहिए, तब इस ऐसा संभव हो सकता है। उनके मुताबिक यदि वहां ऐसा चाहते हैं, तब इसकी प्रक्रिया को भी जल्द ही पूरा भी किया जा सकता है। माना ये भी जा रहा है कि नाटो के बयान पर दोनों देश जल्द ही कोई फैसला भी ले सकते हैं।

बता दें कि यूक्रेन और रूस की जंग के बीच नाटो सबसे बड़ी वजह बन था। ये जंग दूसरे माह भी जारी है। इस कारण 40 लाख से अधिक लोगों को शरणार्थियों का जीवन बिताने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं जंग का असर केवल यहीं तक सीमित नहीं रहा है बल्कि इसकी वजह से समूचे विश्व में तेल और गैस के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इसके अलावा इसकी वजह से

यूक्रेन के पड़ोसी देशों में खाद्य पदार्थों की कमी भी हो गई है। इसके बाद यदि फिनलैंड और स्वीडन नाटो की सदस्यता को लेकर आगे कदम बढ़ाते हैं, तब रूस उनके साथ ही यही व्यवहार कर सकता है, जैसा यूक्रेन के साथ किया है। हालांकि, अब यूक्रेनी राष्ट्रपति कह चुके हैं कि वहां नाटो की सदस्यता के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल चुके हैं। उनके

बयान का अर्थ साफ है कि वहां नाटो के साथ नहीं जा रहे हैं। बावजूद इसके रूस की तरफ से छोड़ी गई जंग का फिलहाल अंत नहीं हुआ है। इस बीच दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। बता दें कि शीत युद्ध के बाद से ही फिनलैंड और स्वीडन तटस्थता नीति को कायम रखे हुए हैं। वहीं फिनलैंड दुनिया का सबसे खुश देश है। ये दोनों ही देश 1995 में यूरोपियन यूनियन में शामिल हुए थे। नाटो के संबंध में फिनलैंड के प्रधानमंत्री का एक बयान बेहद खास माना जा रहा है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि रूस उनकी सोच से अलग है।

शंघाई में कोरोना केस बढ़ने पर अमेरिका ने अपने गैर आपातकालीन कर्मियों को वापस बुलाया

बीजिंग। अमेरिका ने चीन के शंघाई में मौजूद अपने गैर-आपातकालीन सरकारी कर्मचारियों को शहर छोड़ने का आदेश दिया है। शंघाई में कोविड-19 के मामलों में तीव्र वृद्धि के मद्देनजर अमेरिका ने यह कदम उठाया है। शंघाई में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए इस समय कड़ा लॉकडाउन लागू किया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक शंघाई स्थित वाणिज्य दूतावास में गैर-आपातकालीन अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को तुरंत शहर छोड़ने का आदेश दिया गया है। हालांकि, अन्य अमेरिकी अधिकारी वाणिज्य दूतावास में इट्यूटी पर तैनात रहेंगे। चीन की शून्य-कोविड रणनीति के तहत 2.6 करोड़ की आबादी वाले शंघाई में लाखों लोग पिछले तीन सप्ताह से अपने घरों में बंद हैं। शहर में सखी के साथ पृथक्वास के नियम को लागू कर बड़े पैमाने पर जांच की जा रही है। शंघाई में प्रतिबंधों के बीच रह रहे लोगों को निराशाजनक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें उनको अपने घरों से बाहर निकलने की मनाही है और उन्हें भोजन समेत अपनी अन्य दैनिक जरूरतों को पूरा करने में बहुत परेशानी हो रही है। कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए लोगों को बड़े-बड़े सामूहिक पृथक्वास केंद्रों में रखा जा रहा है, जहां हालात बेहद खराब हैं।

पीएम मोदी और बाइडेन की बातचीत के बाद अमेरिका का बड़ा बयान, रूस-यूक्रेन मुद्दे पर भारत अपने फैसले खुद करेगा

कोलंबो। (एजेंसी)

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वरुंअल बैठक हुई। बाइडेन ने भारत के साथ आर्थिक, सामाजिक, सामरिक रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया। बाइडेन ने कहा कि कोरोना के दौरान भारत और अमेरिका ने मिलकर काम किया। डिफेंस के मामले में दोनों देश बड़े पार्टनर हैं। यूक्रेन के लोगों पर रूस की बमबारी पर भारत और अमेरिका यूक्रेन के लोगों के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से कहा गया कि भारत रूस और यूक्रेन से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में अपने फैसले खुद करे।

व्हाइट हाउस की तरफ से बयान देते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका ने राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच

डिजिटल शिखर सम्मेलन के दौरान रूस से तेल आयात के मुद्दे पर भारत से विशेष रूप से कुछ करने के लिये नहीं कहा है। साथ ही उसने यह रेखांकित किया कि भारत रूस और यूक्रेन से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में अपने निर्णय स्वयं लेगा। दोनों नेताओं के बीच डिजिटल बैठक ऐसे समय में हुई है जब यूक्रेन संकट पर भारत के रुख और रियायती दामों पर रूस से तेल खरीदने के उसके फैसले से अमेरिका चिंतित है। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हम भारत के बारे में जानते हैं ... हमने भारत को विशेष रूप से कुछ भी करने के लिए नहीं कहा है। हम बहुत खुली बातचीत कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमने जो किया है, वह सभी देश करने में सक्षम नहीं हैं। अधिकारी ने कहा, जहां तक ऊर्जा से संबंधित मुद्दे की बात है तो यह निश्चित रूप से चर्चा का विषय था।

विश्वविद्यालयों में हिंसा की घटना से बचना चाहिए : यूजीसी चेयरमैन

नई दिल्ली, 12 अप्रैल (एजेन्सी)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हिंसा पर दुख जताया है। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार का इस घटना पर कहना है कि विश्वविद्यालयों में किसी भी प्रकार की हिंसा से बचना चाहिए।

गौरतलब है कि यूजीसी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करती है। इसके अलावा यूजीसी सभी विश्वविद्यालयों के लिए नियम बनाने वाली एक महत्वपूर्ण सरकारी संस्था है। रामनवमी पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में उपद्रव और हिंसा की यह घटना सामने आई थी।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हिंसा की घटना पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जेएनयू से कहा है कि वह मामले की पूरी रिपोर्ट बनाकर मंत्रालय को सौंपे। रविवार को जेएनयू के कावेरी

हॉस्टल में छात्रों के दो समूहों के बीच कहासुनी के बाद तीखी नोकझोंक और फिर मारपीट हुई थी। हिंसा की इस वारदात में जेएनयू के 15 छात्र जख्मी हुए हैं।

रामनवमी के दिन शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन के विवाद से शुरू हुई। छात्रों का एक समूह हॉस्टल के मैन्सू में मांसाहारी भोजन परोसे जाने के पक्ष में था। वहीं दूसरा समूह चाहता था कि हॉस्टल में सभी छात्रों को केवल शाकाहारी भोजन ही परोसा जाए। दोनों समूहों के बीच विवाद होने के बाद हिंसा की घटना देखने को मिली थी।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस हिंसा के बाद छात्रों को चेतावनी दी है कि वे परिसर में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने वाली किसी भी घटना में शामिल हो। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यदि छात्र इस तरह के कृत्यों में लिप्त पाया जाता है तो वे विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई

के लिए उत्तरदायी होंगे।

जेएनयू के कुलपति ने कहा है कि किसी भी प्रकार से बचने के लिए वार्डन तत्काल कदम उठाएं। सुरक्षाकर्मियों को भी इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सतर्क रहने और जेएनयू प्रशासन को तुरंत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

घटना को गंभीरता से लेते हुए कुलपति ने बताया कि परिसर में किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और छात्रों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। छात्र संगठन एबीवीपी ने कहा, रामनवमी के अवसर पर कावेरी छात्रावास में जेएनयू के छात्रों ने एक पूजा का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में जेएनयू के आम छात्रों को बड़ी संख्या में शामिल होना था। यह भी उल्लेखनीय है कि साथ-साथ रमजान भी छात्रावास में बहुत ही शांतिपूर्ण मनाया जा रहा था। यह पूजा 3.30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन वामपंथियों द्वारा किए



गए हंगामे के कारण यह शाम 5.00 बजे शुरू हो सकी। विश्वविद्यालय में इफ्तार और रामनवमी का शांतिपूर्ण उत्सव एक साथ हो रहा था।

हालांकि वामपंथी इस तथ्य को पचा नहीं पाते हैं। उन्होंने 'मांसाहारी भोजन' का मुद्दा उल्लंघन करने के बीच हंगामा करने की योजना बनाई। वाम समर्थित छात्र संघ एसएफआई ने कहा, हम एबीवीपी द्वारा जानबूझकर परिसर के माहौल

को बाधित करने के प्रयास की निंदा करते हैं। असामाजिक तत्व कावेरी हॉस्टल में और उसके आसपास दंगा करते रहे, बाइक तोड़ते रहे, हॉस्टल और छात्रों को पीटते रहे। पुलिस मौके पर पहुंच गई है लेकिन छात्रों के अनुरोध के बावजूद कुछ भी करने से इनकार कर दिया। हम जेएनयू के छात्रों से नैतिक पुलिसिंग, संप्रदायिकता को हराने के लिए एकजुट होने की अपील करते हैं।

मरने से पहले कॉन्ट्रैक्टर ने मंत्री ईश्वरप्पा पर लगाए आरोप, बताया मौत का जिम्मेदार

बेंगलुरु, 12 अप्रैल (एजेन्सी)। कर्नाटक में एक कॉन्ट्रैक्टर की मौत से वहां की राजनीति में भूचाल आ गया है। यह सब तब हुआ है जब कर्नाटक के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा पर एक ठेके लिए 40 फीसदी कमीशन मांगने का आरोप लगाने वाले कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार ने कथित तौर पर सुसाइड कर लिया है। उसने सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिए सीधे-सीधे मंत्री को जिम्मेदार बताया है।

दरअसल, यह घटना मंगलवार की है जब सुबह सुबह उड़पी के एक लॉज में संतोष पाटिल नामक ठेकेदार की लाश मिली। अपनी मौत से पहले पाटिल ने कुछ संदेश भेजे हैं जिसमें कहा गया है कि वह आत्महत्या कर रहा है और आरोप लगाया कि उसकी मृत्यु के लिए ईश्वरप्पा जिम्मेदार हैं। इतना ही नहीं उसने यह भी लिखा कि मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और हमारे प्रिय लिंगायत नेता से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि मेरी पत्नी और बच्चों की मदद करें।

पुलिस ने बताया कि यह खुदकुशी का मामला हो सकता है। बताया जा रहा है कि संतोष पाटिल ने कर्नाटक राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा था जिसमें आरोप लगाया गया था कि मंत्री और उनके सहयोगी उन्हें परेशान कर रहे थे।

वहीं इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए ईश्वरप्पा ने कहा कि उन्हें आत्महत्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अपने इस्तीफे की बात पर उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने संतोष पाटिल के खिलाफ जो मामला दायर कराया है, हमें अदालत में उसका फैसला आने का इंतजार करना होगा। मैं यह बिल्कुल स्पष्ट करता हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है।

ईश्वरप्पा ने यह भी कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मौत से पहले लिखे नोट में मेरा नाम क्यों लिखा और उन्होंने मुझ पर आरोप क्यों लगाया है। इसका जवाब तो सिर्फ वह ही दे सकते थे।

खास दुकान से किताब और यूनिफॉर्म खरीदने को नही बोल सकते प्राइवेट स्कूल, पंजाब सरकार का आदेश



नई दिल्ली, 12 अप्रैल (एजेन्सी)। पंजाब में भगवंत मान की आप सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर डंडा चलाना शुरू कर दिया है। पंजाब सरकार ने आर्डर जारी कर सभी प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया है कि वो बच्चों के माता-पिता की किसी खास दुकान से स्कूल की किताबें या यूनिफॉर्म लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। आप सरकार ने पंजाब के सभी प्राइवेट स्कूलों से कहा है कि वो इस नियम का सख्ती से पालन करें। पंजाब सरकार ने आर्डर में कहा है- पंजाब के सभी प्राइवेट स्कूलों को उन दुकानों की लिस्ट जारी करनी होगी जहां से बच्चे किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं। ये लिस्ट जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी भेजी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी इन दुकानों पर टीम भेजकर जांच करवाएंगे। ये टीम किसी भी समय

जाकर इन दुकानों को वेरिफाई करेगी कि यहाँ वो सामान मिल रहा है या नहीं। अगर पता चलता है कि स्कूल ने गलत नाम दे दिया है तो स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आर्डर में ये भी लिखा है कि अगर स्कूल के यूनिफॉर्म के डिजाइन में कुछ चेंज किया जाता है तो पुराने बच्चों को नई ड्रेस खरीदने के लिए दो साल का समय देना होगा। तबतक पुरानी ड्रेस के साथ बच्चों को स्कूल में आने की इजाजत होगी। आप सरकार ने पंजाब के सभी प्राइवेट स्कूलों को आर्डर की कॉपी भेज दी है। पंजाब के शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह हायर पंजाब के प्राइवेट स्कूलों की स्थिति का जायजा ले रहे हैं या नहीं। जो स्कूल आप सरकार के इन आदेशों का पालन नहीं कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी टीम का गठन कर दिया गया है।

शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय प्रशासन से तलब की रिपोर्ट

नई दिल्ली, 12 अप्रैल (एजेन्सी)। रामनवमी के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में हुए उपद्रव और हिंसा की घटना पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जेएनयू से कहा है कि वह मामले की पूरी रिपोर्ट बनाकर मंत्रालय को सौंपे।

रविवार को जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में छात्रों के दो समूहों के बीच कहासुनी के बाद तीखी नोकझोंक और फिर मारपीट हुई थी। हिंसा की इस वारदात में जेएनयू के 15 छात्र जख्मी हुए हैं।

दरअसल यह घटना रामनवमी के दिन शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन के विवाद से शुरू हुई। छात्रों का एक समूह हॉस्टल के मैन्सू में मांसाहारी भोजन परोसे जाने के पक्ष में था। वहीं दूसरा समूह चाहता था कि हॉस्टल में सभी छात्रों को केवल शाकाहारी भोजन ही परोसा जाए।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस हिंसा के बाद छात्रों को चेतावनी दी है कि वे परिसर में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने वाली किसी भी घटना में शामिल हो। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यदि छात्र

इस तरह के कृत्यों में लिप्त पाया जाता है, तो वे विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। जेएनयू के कुलपति ने कहा है कि किसी भी प्रकार से बचने के लिए वार्डन तत्काल कदम उठाएं। सुरक्षाकर्मियों को भी इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सतर्क रहने और जेएनयू प्रशासन को तुरंत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

घटना को गंभीरता से लेते हुए कुलपति ने बताया कि परिसर में किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और छात्रों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। छात्र संगठन एबीवीपी ने कहा, रामनवमी के अवसर पर कावेरी छात्रावास में जेएनयू के छात्रों ने एक पूजा का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में जेएनयू के आम छात्रों को बड़ी संख्या में शामिल होना था। यह भी उल्लेखनीय है कि साथ-साथ रमजान भी छात्रावास में बहुत ही शांतिपूर्ण मनाया जा रहा था। यह पूजा 3.30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन वामपंथियों द्वारा किए गए हंगामे के कारण यह शाम 5.00 बजे शुरू हो सकी। विश्वविद्यालय में इफ्तार और रामनवमी का शांतिपूर्ण उत्सव एक साथ हो रहा था। हालांकि वामपंथी इस तथ्य को पचा नहीं पाते हैं। उन्होंने 'मांसाहारी भोजन' का मुद्दा उल्लंघन करने की योजना बनाई। वाम समर्थित छात्र संघ एसएफआई ने कहा, हम एबीवीपी द्वारा जानबूझकर परिसर के माहौल को बाधित करने के प्रयास की निंदा करते हैं। असामाजिक तत्व कावेरी हॉस्टल में और उसके आसपास दंगा करते रहे, बाइक तोड़ते रहे, हॉस्टल और छात्रों को पीटते रहे। पुलिस मौके पर पहुंच गई है लेकिन छात्रों के अनुरोध के बावजूद कुछ भी करने से इनकार कर दिया। हम जेएनयू के छात्रों से नैतिक पुलिसिंग, संप्रदायिकता को हराने के लिए एकजुट होने की अपील करते हैं।

आईएनएस विक्रांत धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस ने किरीट सोमैया को जारी किया समन

मुंबई, 12 अप्रैल (एजेन्सी)। आईएनएस विक्रांत धोखाधड़ी मामले में मुंबई पुलिस ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया को इकनॉमी ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) के सामने पेश होने का समन जारी किया है। किरीट सोमैया और उनके बेटे पर आईएनएस विक्रांत को बचाने के नाम पर 57 करोड़ रुपये चंदा जमा करने का आरोप है। इस मामले में केस दर्ज होने के बाद अब किरीट सोमैया से पूछताछ की तैयारी चल रही है। पुलिस ने किरीट सोमैया से बुधवार को ईओडब्ल्यू के सामने पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि मंगलवार को किरीट सोमैया ने अपने खिलाफ लगे इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उन्होंने सिर्फ 11 हजार रुपये जमा किए थे जो उन्होंने पार्टी फंड में जमा कर दिए।

गौरतलब है कि इस मामले पर सुनवाई के दौरान मुंबई की सेरेंस कोर्ट ने किरीट सोमैया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टा उनके खिलाफ मामला बनता है। कोर्ट ने



इस मामले में किरीट सोमैया के बेटे नील की भी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। ट्रीबे पुलिस ने पूर्व कर्मचारी की शिकायत पर किरीट सोमैया और उनके बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि किरीट सोमैया और उनके बेटे ने आईएनएस विक्रांत को स्कूप में जाने से बचाने और उसे म्यूजियम में रखने के नाम पर 57 करोड़ रुपये चंदा जमा किया और उसे हड़प कर गए। भारतीय नौ सेना के विमान

आईएनएस विक्रांत ने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1961 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए आईएनएस विक्रांत को नेवी ने 1997 में डिक्मिशन कर दिया था। इसके बाद आईएनएस विक्रांत को स्कैप ना करते हुए उसे म्यूजियम में रखने की मांग उठी थी लेकिन वो मांग पूरी नहीं हो सकी और जनवरी 2014 को जहाज बेच दिया गया और नवंबर में उसे स्कूप कर दिया गया। मंगलवार को किरीट सोमैया ने

कुपोषण अक्सर ज्ञान की कमी का परिणाम होता है : पीएम मोदी



राजेश अलख नई दिल्ली, 12 अप्रैल। संतुलित आहार के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि कुपोषण अक्सर भोजन की कमी के बजाय भोजन के बारे में जानकारी की कमी का परिणाम होता है।

मोदी ने गुजरात के अदलज में श्री अन्नपूर्णाधाम ट्रस्ट के छात्रावास और शिक्षा परिसर का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान जनसहायक ट्रस्ट के हीरामनी आरोग्यधाम का भूमिपूजन भी किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल भी मौजूद थे।

उन्होंने कहा, 'स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के क्षेत्र में योगदान देना गुजरात का स्वभाव रहा है। सभी समुदाय अपनी क्षमता के अनुसार अपनी भूमिका निभाते हैं और पाटीदार समुदाय समाज के लिए अपनी भूमिका निभाने में कभी

पीछे नहीं रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समृद्धि की देवी मां अन्नपूर्णा को सभी और विशेष रूप से पाटीदार समुदाय द्वारा गहरा सम्मान दिया जाता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी की वास्तविकताओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, 'मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा हाल ही में कनाडा से काशी वापस लाई गई थी। हमारी संस्कृति के ऐसे दर्जनों प्रतीक पिछले कुछ वर्षों में विदेशों से वापस लाए गए हैं।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति में भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा को हमेशा बहुत महत्व दिया जाता है और आज श्री अन्नपूर्णाधाम ने इन तत्वों का विस्तार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने जिला अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा शुरू की है। प्रधानमंत्री ने आगे गुजरात में विकास की समृद्ध परंपरा का उल्लेख किया जहां विकास के नए मानक

रखे गए हैं। विकास की इस परंपरा को मुख्यमंत्री आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' में भारत ने सरदार पटेल को बड़ी श्रद्धांजलि दी है, जिनका नाम पूरी दुनिया में पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मां अन्नपूर्णा की भूमि गुजरात में कुपोषण के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अक्सर कुपोषण अज्ञानता के कारण होता है। उन्होंने संतुलित आहार के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया।

भोजन को स्वास्थ्य की दिशा में पहला कदम बताते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि कुपोषण अक्सर भोजन की कमी के बजाय भोजन के बारे में ज्ञान की कमी का परिणाम होता है। प्रधानमंत्री ने आगे उल्लेख किया कि महामारी के दौरान, सरकार ने 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान्न सुनिश्चित किया।

कोर्ट में बोले एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख, क्या मैं नीरव मोदी या विजय माल्या लगता हूँ?

नई दिल्ली, 12 अप्रैल (एजेन्सी)। एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल को कुछ दिन पहले बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था और अमेरिका जाने से रोक दिया गया था। सीबीआई ने बताया था कि उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। मंगलवार को सीबीआई ने दिल्ली कोर्ट में कहा कि वह कई मामलों में आरोपी हैं। इसपर पटेल के वकील ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से कहा जा सके कि उनके देश छोड़कर भागने का खतरा है।

आकार पटेल ने कोर्ट से कहा, क्या मैं नीरव मोदी या विजय माल्या हूँ? कोर्ट में उनके खिलाफ लुकआउट सफुल्यत जारी करने को लेकर सुनवाई चल रही थी। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि आकार पटेल पर मुकदमा चलाने के लिए उनपर प्रतिबंध लगाए गए हैं। सीबीआई की तरफ से पेश हुए वकील निखिल गोयल ने कहा कि वह कई मामलों में शामिल हैं। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि एफआईआर में आकार पटेल का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि वहां उनके संगठन का नाम लिखा गया है। उन्होंने कहा, पटेल ही संगठन को चलाते थे। उनके संगठन में विदेशी धन केवल एमनेस्टी यूके से नहीं बल्कि अन्य संगठनों से भी आता था।



सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि एफआईआर में आकार पटेल का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि वहां उनके संगठन का नाम लिखा गया है। उन्होंने कहा, पटेल ही संगठन को चलाते थे। उनके संगठन में विदेशी धन केवल एमनेस्टी यूके से नहीं बल्कि अन्य संगठनों से भी आता था।

सीबीआई के तर्कों का जवाब देते हुए पटेल के वकील ने कहा कि पटेल बांग्लादेश गए और वहां से भी लौट आए। पटेल की तरफ से उन्होंने कहा, मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूँ। मुझे दूसरे देश जाने का भी टिकट मिला लेकिन मैंने नहीं लिया। यह मेरा फैसला था। बता दें कि पटेल को सीबीआई के लुकआउट सफुल्यत की वजह से एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था। बाद में सीबीआई ने कोर्ट में इसके लिए माफी भी मांगी।

भारत में मानवाधिकारों के हनन पर नजर रखे हुए है अमेरिका : ब्लिंकन



नई दिल्ली, 12 अप्रैल (एजेन्सी)। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका भारत में मानवाधिकारों के हनन की घटनाओं में वृद्धि पर नजर रखे हुए है। टीआरटी वलूड की रिपोर्ट ने बात कही गई है।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन ने कहा 'हम इन साझा मूल्यों (मानवाधिकारों के) पर भारत के साथ नियमित रूप से बात करते हैं और हम भारत में हाल में घटी उन घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं, जिसमें सरकार, पुलिस और जेल अधिकारियों द्वारा मानवाधिकारों का हनन शामिल है', ब्लिंकन ने सोमवार को अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन, भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में ये बात कही। हालांकि ब्लिंकन ने विस्तार से

नहीं बताया कि वो किन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। प्रेस ब्रीफिंग में ब्लिंकन के बाद बोलने वाले राजनाथ सिंह और जयशंकर ने मानवाधिकार के मुद्दे पर ब्लिंकन के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की। ब्लिंकन की टिप्पणी से कुछ दिन पहले ही अमेरिकी प्रतिनिधि इल्हान उमर ने मानवाधिकार के मुद्दों पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना करने से अमेरिका के बचने पर सवाल उठाए थे।

'मोदी को भारत की मुस्लिम आबादी के साथ क्या करने की जरूरत है? अगर कुछ नहीं किया गया तो क्या हम शांति में भारत को भागीदार मानना बंद कर देंगे?' राष्ट्रपति जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले उमर ने पिछले हफ्ते ये बात कही थी।